@saahassamachar @saahassamachar @saahassamachar

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

साहस समाचार

निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक

नई दिल्ली, बुधवार, 16 सितंबर 2026, वर्ष-1, अंक-288, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए RNI No-DLHIN/25/A2841 www.saahassamachar.in

रोहित रॉय के 'डस्टबिन मीडियम' वाले बयान से चाहत सहमत

...पेज-8

किशाऊ परियोजना पर अमित शाह की अध्यक्षता में छह राज्यों में हुआ करार

नई दिल्ली,एजेंसी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य भवन में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मंगलवार को लगभग आठ दशकों से प्रतीक्षित इस परियोजना के लिए हुआ यह समझौता जल सुरक्षा, ऊर्जा, सिंचाई, पेयजल तथा यमुना के पुनर्जीवीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं निर्णायक कदम है। इस दौरान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखण्ड की ओर से केन्द्र सरकार सहित सभी सहभागी राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि किशाऊ परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1940 में की गई थी। इतने लंबे समय में परियोजना को आगे बढ़ाने के अनेक प्रयास हुए लेकिन विभिन्न कारणों से यह परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज दशकों से लंबित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से श्री शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में 16 जून 2026 की बैठक में परियोजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अड़चनों के

समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ।

इसके बाद केंद्र एवं सहभागी राज्य सरकारों के बीच निरंतर समन्वय से परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई और आज एमओयू पर हस्ताक्षर के साथ इसे औपचारिक रूप दिया गया है। धामी ने कहा कि किशाऊ कोई सामान्य बांध परियोजना नहीं है, बल्कि यह जल सुरक्षा, ऊर्जा, सिंचाई, पेयजल और यमुना के पुनर्जीवीकरण से जुड़ी राष्ट्रीय महत्व की बहुउद्देशीय परियोजना है। उन्होंने कहा कि परियोजना से लगभग 1562 एमसीएम क्षमता का विशाल जलाशय बनेगा तथा 422 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित होगी। इसका लाभ उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित पूरे अपर यमुना बेसिन को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ परियोजना केवल एक राज्य या क्षेत्र की परियोजना नहीं है, बल्कि यह अंतरराज्यीय सहयोग और सहकारी संघवाद का महत्वपूर्ण उदाहरण है। केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयासों तथा सहभागी राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से दशकों से लंबित परियोजना को अब निर्णायक गति मिली है। उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी सामने आएंगी।

परियोजना से प्रभावित परिवारों का उचित, संवेदनशील एवं सम्मानजनक पुनर्वास उत्तराखण्ड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के साथ प्रभावित परिवारों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करना आवश्यक है और राज्य सरकार इस दिशा में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगी। धामी ने कहा कि परियोजना के लिए लगभग 2500 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण की आवश्यकता होगी।

इसके कारण क्षतिपूरक वनीकरण के लिए बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे वनाच्छादित और पर्वतीय राज्य के लिए इतनी बड़ी मात्रा में भूमि उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

सार समाचार

शिवसेना में विभाजन मामले में न्यायालय ने सुनवाई फिर शुरू की

नई दिल्ली,एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई फिर से शुरू की। सुनवाई के दौरान शिंदे धड़े ने निर्वाचन आयोग के उस फैसले का बचाव किया, जिसमें उसे ''असली'' शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े की उस याचिका पर भी सुनवाई कर रही है जिसमें निर्वाचन आयोग के 17 फरवरी, 2023 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत शिवसेना नाम और उसका 'धनुष-बाण' चुनाव चिह्न शिंदे धड़े को आवंटित किया गया था। शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कहा कि निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किसी राजनीतिक दल के संविधान और संगठनात्मक ढांचे के लोकतांत्रिक स्वरूप की जांच करने का अधिकार है।

दिल्ली में 10 हजार विद्यार्थियों के लिए बनेंगे हॉस्टल: रेखा गुप्ता

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10 हजार विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल का निर्माण करेगी। गुप्ता ने कहा कि इन छात्रावासों का निर्माण विभिन्न विभागों के माध्यम से कराया जायेगा और आवश्यकता पड़ने पर जमीन लेकर भी हॉस्टल बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि छात्राओं और छात्रों, दोनों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ एक बड़ा शिक्षा केंद्र भी है।

देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में युवा उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आते हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सुरक्षित और किफायती आवास की व्यवस्था करना होती है। सरकार इसी समस्या का स्थायी समाधान तलाश रही है। दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के अलावा दिल्ली के किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।

पहाड़ों से रेगिस्तान तक भारत-अमेरिका की सेनाओं का 'युद्ध अभ्यास'

नई दिल्ली, एजेंसी।

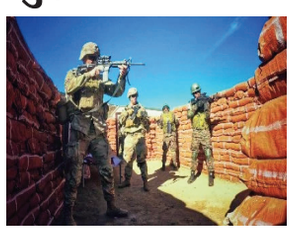

भारत और अमेरिका की सेनाएं एक बार फिर साथ मिलकर युद्ध कौशल और आधुनिक तकनीक की ताकत परख रही हैं। दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'युद्ध अभ्यास 2026' का 22वां संस्करण मंगलवार को शुरू हुआ।

इस बार इसकी खास बात यह है कि अभ्यास उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाके औली से लेकर राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज तक एक साथ चल रहा है। औली में 14 इन्फैंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अमरेश गुंजन ने जवानों से संवाद किया। वहीं अमेरिकी सेना की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की पहली इन्फैंट्री ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के कमांडर कर्नल बेंजामिन जैकमैन ने भी सैनिकों को संबोधित किया। अभ्यास में भारत और अमेरिका के करीब 600-600 सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं।

इस अभ्यास में दोनों सेनाएं पहाड़ी और अर्ध-पहाड़ी इलाकों में एकीकृत युद्ध समूहों के संचालन की क्षमता को मजबूत करेंगी। खास तौर पर पैदल सेना आधारित अभियानों पर ध्यान दिया जाएगा। सैनिक अलग-अलग परिस्थितियों में एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाकर अभियान चलाने की रणनीति और तकनीक का अभ्यास करेंगे। 'युद्ध अभ्यास 2026' में आधुनिक तकनीक भी केंद्र में है। सैनिक निगरानी और टोह लेने के लिए ड्रोन और स्वायत्त प्रणालियों का इस्तेमाल करेंगे। वहीं, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाएगा।

डूसू चुनाव में लिंगदोह रिपोर्ट के उल्लंघन का आरोप

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक दलों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के आगामी चुनाव में विभिन्न पदों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र द्वारा दायर जनहित याचिका में मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से जारी 11 सितंबर और 13 अगस्त के नोटिसों को चुनौती दी गई है, जिनमें डूसू चुनावों की घोषणा की गई थी और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम 'शॉर्टलिस्ट' किए गए थे।

याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के छात्र विंग के सदस्यों को डूसू चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसपर लिंग्दोजह समिति की रिपोर्ट के तहत प्रतिबंध लगा हुआ है।

यूपीआई भुगतान पर लगेगा 0.4 प्रतिशत शुल्क, 15 अक्टूबर से लागू

2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर व्यापारियों से 0.4 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा

नई दिल्ली, एजेंसी।

सरकार ने मंगलवार को 15 अक्टूबर से बड़े व्यापारी भुगतान के लिए यूपीआई लेनदेन पर नई शुल्क व्यवस्था लागू करने की घोषणा की। इसके तहत 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर व्यापारियों से 0.4 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा जबकि 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी। भुगतान करने वाले ग्राहकों को यह शुल्क नहीं देना होगा और इसका बोझ दुकानदार या व्यापारी को उठाना पड़ेगा। हालांकि, दो व्यक्तियों के बीच होने वाले पी2पी यूपीआई भुगतान पर किसी भी राशि के लिए कोई एमडीआर शुल्क नहीं लगेगा।

इसके अलावा 2,000 रुपये तक के छोटे व्यापारी लेनदेन भी शुल्क से बाहर रहेंगे। सरकार के मुताबिक, व्यक्तियों से व्यापारियों को होने वाले कुल पी2एम लेनदेन की मात्रा में 2,000 रुपये से कम राशि वाले लेनदेन 95 प्रतिशत से भी अधिक हैं। 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले किसी व्यापारी से लिया जाता है। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, यह शुल्क केवल 2,000 रुपये से अधिक के पी2एम लेनदेन पर ही 0.4 प्रतिशत की दर से लागू होगा। इससे मिलने वाला कमीशन बैंकों और ऐप प्रदाताओं सहित भुगतान प्रणाली के भागीदारों के बीच बांटा जाएगा।

रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि कच्चा माल जैसे आवश्यक तथा कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के प्रत्येक लेनदेन पर पांच रुपये का एक समान शुल्क लगेगा। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण सेवाओं की लागत को विश्वसनीय बनाए रखना है। इन श्रेणियों की हिस्सेदारी पी2एम लेनदेन की मात्रा में करीब 17 प्रतिशत, जबकि लेनदेन के मूल्य में लगभग 46 प्रतिशत है। यही समान शुल्क व्यवस्था सरकारी उपयोगिता बिलों (बिजली, पानी और पाइप वाली गैस) के भुगतान तथा स्कूल फीस और विश्वविद्यालय शुल्क जैसे शैक्षणिक भुगतान पर भी लागू होगी। हालांकि 2,000 रुपये तक के ऐसे भुगतान इस शुल्क से मुक्त रहेंगे।

म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों तथा शेयर ब्रोकर और डीलर के जरिये किए जाने वाले भुगतान पर 0.02 प्रतिशत एमडीआर लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी। सरकार ने कहा कि यूपीआई ऐप प्रदाताओं को डिजिटल मंच शुल्क या छिपे हुए शुल्क लगाने की अनुमति नहीं होगी। बैंकों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि व्यापारी इस नए शुल्क का बोझ ग्राहकों पर न डालें। इसके अलावा, व्यक्तिगत यूपीआई लेनदेन के लिए कोई मासिक कोटा या मुफ्त लेनदेन की संख्या पर सीमा नहीं होगी।

यूपीआई क्यूआर कोड के जरिये हर महीने एक लाख रुपये तक पाने वाले छोटे व्यापारी नई व्यवस्था के तहत शून्य एमडीआर का लाभ लेते रहेंगे। यदि कोई व्यापारी लगातार तीन महीने तक एक लाख रुपये से अधिक का मासिक लेनदेन करता है, तो उसे सामान्य पी2एम श्रेणी में रखा जाएगा। सरकार के अनुसार, नई व्यवस्था से केवल करीब चार प्रतिशत व्यापारी लेनदेन ही प्रभावित होंगे। इसकी वजह है कि अधिकांश लेनदेन या तो 2,000 रुपये की सीमा से कम हैं या पी2एम छूट के दायरे में आते हैं। नई एमडीआर व्यवस्था केवल प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता के बैंक खाते से व्यापारी के खाते में होने वाले यूपीआई भुगतान पर लागू होगी। यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड या पहले से मंजूर 'क्रेडिट लाइन' के जरिये होने वाले भुगतान अलग नियमों के तहत आएंगे। वहीं, यूटिलिटी बिल, ओटीटी सदस्यता और नियमित निवेश के लिए यूपीआई निर्देश या ऑटोपे जैसे स्वचालित आवर्ती भुगतान पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा।

यूपीआई लेनदेन पर लगा मोदी टैक्स: कांग्रेस

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क को मंगलवार को मोदी टैक्स करार दिया और आरोप लगाया कि कम्प्रोमाइज्ड (समझौता कर चुके) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने व्यापार समझौते की तरह इस मामले में भी अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह दावा भी किया कि 2,000 रुपये से अधिक के व्यापारिक यूपीआई लेनदेन की संख्या भले ही करीब पांच प्रतिशत हो, लेकिन यूपीआई के कुल लेनदेन मूल्य में इनकी हिस्सेदारी करीब 65 प्रतिशत है तथा उसका बोझ अंततः कीमतों में बढ़ोतरी के जरिये ग्राहकों की जेब पर ही पड़ेगा।

सरकार ने मंगलवार को बड़े डिजिटल भुगतान के लिए जारी नई व्यवस्था के तहत 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पाने पर व्यापारियों से 0.4 प्रतिशत का एमडीआर शुल्क लेना तय किया। इसमें 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर अधिकतम शुल्क 300 रुपये होगा। इसके साथ जनवरी, 2020 से लागू शून्य-एमडीआर व्यवस्था समाप्त हो गई है। इस व्यवस्था को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था, लेकिन बैंक और वित्तीय-प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनियां लंबे समय से इस पर सवाल उठा रही थीं। आधिकारिक बयान के मुताबिक, नए बदलाव 15 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी हो जाएंगे।

कांग्रेस यूपीआई शुल्क के बारे में फैला रही फर्जी खबर: भाजपा

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस पर यूपीआई लेनदेन शुल्क के बारे में फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि लोगों पर 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

यह घटनाक्रम उस वक्त हुआ, जब कांग्रेस ने यूपीआई लेनदेन पर जारी अधिसूचना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुपके से ऐसे लेनदेन पर शुल्क लगाने का रास्ता खोल दिया है और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की तरह ही, कम्प्रोमाइज्ड (समझौता कर चुके) प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव में समर्पण कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए विपक्षी पार्टी को झूठ की दुकान कहा।

उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''कांग्रेस एक बार फिर झूठी खबरें फैला रही है। 96 प्रतिशत यूपीआई मर्चेंट (पी2एम) लेनदेन 2,000 रुपये या उससे कम के होते हैं और उन पर कोई शुल्क नहीं लगता। रुपे डेबिट-कार्ड से भुगतान करने पर भी कोई शुल्क नहीं लगता। ग्राहकों को लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। 'पी2पी' यूपीआई लेनदेन पूरी तरह से निशुल्क है।

'पी2एम' लेनदेन एक तरह का डिजिटल भुगतान है और इसके तहत उपयोगकर्ता खुदरा विक्रेता या सेवा प्रदाता को रकम अदा करता है, जबकि 'पी2पी' लेनदेन के तहत मोबाइल फोन के जरिये एक व्यक्ति के बैंक खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा भेजा जाता है। भंडारी ने कहा, सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ग्राहकों से एमडीआर शुल्क नहीं लिया जाएगा।

सरकार ने बैंकों और भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन या रुपे डेबिट कार्ड के जरिये किए गए भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाने का निर्देश दिया है।

जब किसी डीलर द्वारा परिवहन वाहन बेचा जाए तो यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था हो कि उसमें एसएलडी या एसएलएफ लगा हुआ है

वाहनों में 'स्पीड गवर्नर' लगाने के नियम का अनुपालन सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,एजेंसी।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को परिवहन वाहनों में 'स्पीड गवर्नर' लगाने संबंधी नियम का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली (सीएमवीआर), 1989 के नियम 118 का उल्लेख किया, जिसमें अधिसूचित परिवहन वाहनों में 'स्पीड गवर्नर' लगाने का प्रावधान है। 'स्पीड गवर्नर' एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल सुरक्षा उपकरण है, जिसे गाड़ियों (विशेषकर व्यावसायिक वाहनों जैसे बसों, ट्रकों और टैक्सियों) में उनकी अधिकतम गति को सीमित करने के लिए लगाया जाता है।

सड़क सुरक्षा मानकों के अनुपालन के अनुरोध से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत ने 13 मई को कहा था कि सभी वाहन निर्माता विनिर्माण के समय 'स्पीड लिमिटिंग डिवाइस' (एसएलडी) लगाने के लिए बाध्य हैं। न्यायालय ने तब केंद्र को परिवहन वाहनों के विनिर्माण या उनकी आपूर्ति के समय एसएलडी लगाने के मुद्दे पर वाहन निर्माताओं के साथ बैठक करने को कहा था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि केंद्र ने एक हलफनामा दाखिल करके कहा है कि इस संबंध में जून में एक बैठक आयोजित की गई थी।

पीठ ने कहा, जहां तक स्पीड गवर्नर का सवाल है, हमारा मत है कि नियम, विशेष रूप से केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 का नियम 118, स्वयं अधिसूचित परिवहन वाहनों में एसएलडी/एसएलएफ (स्पीड लिमिटिंग फंक्शन) लगाने को अनिवार्य करता है। पीठ ने कहा, हम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से ऊपर उल्लिखित नियम 118 का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र के साथ-साथ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जब किसी डीलर द्वारा परिवहन वाहन बेचा जाए तो यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था हो कि उसमें एसएलडी या एसएलएफ लगा हुआ है। पीठ ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सार्वजनिक सेवा वाहनों में वाहन 'लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस' पहले से लगाए जाने के संबंध में वाहन निर्माताओं के साथ हुई बातचीत की रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। उसने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सीएमवीआर, 1989 के नियम 125एच के अनुपालन की वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। नियम 125एच के तहत सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में वाहन 'लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस' और आपातकालीन बटन होना अनिवार्य है।

तेरह मई को मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस बात को ''चिंताजनक'' बताया था कि एक प्रतिशत से भी कम परिवहन वाहनों में वाहन 'लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस' लगा है। उसने कहा था कि यह उपकरण यात्रियों, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अदालत ने यह सुझाव दिए जाने के बाद कि यह उपकरण वाहन निर्माता द्वारा ही लगाया जाना चाहिए, पीठ ने मई में केंद्र को वाहन निर्माताओं के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने और अदालत को जानकारी देने का निर्देश दिया था।

भारत ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हराकर टी20 सीरीज पर जमाया कब्जा

नई दिल्ली, साहस समाचार।

अफगानिस्तान ने 159 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर भारत के सामने मुश्किल लक्ष्य रखने की कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरते ही मुकाबले का रुख बदल दिया। संजू सैमसन के बल्ले से निकले चौकों-छक्कों के तूफान और अभिषेक शर्मा की आक्रामक शुरुआत ने अफगानिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह बेअसर कर दिया। इससे पहले नीतीश कुमार रेड्डी और अर्शदीप सिंह की धारदार गेंदबाजी ने अफगानिस्तान को बड़े स्कोर से रोक दिया था। भारत ने मंगलवार को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अफगानिस्तान को सात विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया।

160 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने महज 14.5 ओवर में तीन विकेट पर 163 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज की। संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर 57 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें सात चौके और चार छक्के शामिल रहे। वहीं अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर 39 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए केवल 6.2 ओवर में 88 रन की साझेदारी कर भारत की जीत की मजबूत नींव रखी। अभिषेक शर्मा ने पावरप्ले में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। सैमसन ने शुरुआत में संभलकर खेलने के बाद अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने मोहम्मद नबी के एक ओवर में तीन छक्के और दो चौके लगाकर 27 रन बटोरे। इसके बाद सैमसन ने महज 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।

दुल्हनों की तस्वीर भेजकर ठगी, वकील समेत 8 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, गिरोह फर्जी वैवाहिक जालस्थल के माध्यम से देशभर में शादी के इच्छुक पुरुषों को निशाना बनाता था।

नई दिल्ली,एजेंसी।

शादी के लिए रिश्ता तलाश रहे पुरुषों को फर्जी वैवाहिक सेवा के नाम पर ठगने वाले एक संगठित गिरोह का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मध्य जिले की साइबर थाना पुलिस ने आगरा में चल रहे एक कथित ठगी केंद्र का भंडाफोड़ कर अधिवक्ता अमित कुमार समेत 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें कंपनी की प्रबंधक जया शाक्य और 7 महिला दूरभाष संचालक शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, गिरोह फर्जी वैवाहिक जालस्थल के माध्यम से देशभर में शादी के इच्छुक पुरुषों को निशाना बनाता था।

जांच में सामने आया है कि आरोपित पहले पुरुषों को आकर्षक संभावित दुल्हनों की तस्वीरें भेजते थे। इसके बाद फोन पर बातचीत करवाकर उन्हें भरोसे में लिया जाता था। जब व्यक्ति रिश्ते में रुचि दिखाता, तो पंजीकरण शुल्क, परिचय पत्र देखने का शुल्क, परिचय पत्र सक्रिय करने का शुल्क और संपर्क संख्या उपलब्ध कराने के नाम पर अलग-अलग रकम मांगी जाती थी। पुलिस के मुताबिक, गिरोह 'शादीपार्टनर.कॉम' नाम से वैवाहिक सेवा चलाने का दावा करता था। इसी नाम से बनाए गए जालस्थल के माध्यम से लोगों को शादी के लिए उपयुक्त रिश्ता दिलाने का झांसा दिया जाता था।

एक पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर अपराध सूचना मंच पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जालस्थल के जरिए शादी के लिए रिश्ता दिलाने का वादा कर उससे पैसे ऐंठे गए। जांच शुरू होने के बाद पुलिस को पता चला कि यह किसी एक व्यक्ति के साथ हुई ठगी का मामला नहीं, बल्कि देशभर में फैले संगठित गिरोह का हिस्सा है। पुलिस को अब तक इस गिरोह से जुड़ी 6 शिकायतें मिल चुकी हैं। अधिकारियों को आशंका है कि पिछले करीब 1 वर्ष के दौरान गिरोह ने बड़ी संख्या में शादी के इच्छुक पुरुषों को अपना शिकार बनाया है। गिरोह का तरीका सुनियोजित था।

पहले पीड़ित के वाट्सएप पर संभावित दुल्हन की आकर्षक तस्वीरें भेजी जाती थीं। इसके बाद उसे विश्वास दिलाने के लिए दूरभाष पर बातचीत कराई जाती थी। कई मामलों में संभावित दुल्हन से सीधे बातचीत कराने का नाटक भी किया जाता था, ताकि पूरी प्रक्रिया वास्तविक वैवाहिक संबंध जैसी लगे। पीड़ित के रिश्ते में रुचि दिखाने के बाद उससे अलग-अलग चरणों में रकम जमा कराई जाती थी। एक शिकायतकर्ता से पंजीकरण शुल्क, परिचय पत्र देखने का शुल्क, परिचय पत्र सक्रिय करने का शुल्क और संपर्क संख्या उपलब्ध कराने के नाम पर कुल 15 हजार रुपये वसूले गए। पुलिस ने ठगी की रकम के लेन-देन की जांच की तो पता चला कि पैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक चालू खाते में जमा कराए गए थे।

यह खाता 'शादीपार्टनर.कॉम' नाम की व्यावसायिक इकाई के नाम पर पंजीकृत था। बैंक संबंधी अभिलेख और पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच में जया शाक्य उर्फ शशि को इस खाते की एकमात्र स्वामिनी और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पाया गया।

दुबई की दो उड़ानों में काफी देरी होने पर यात्रियों ने किया प्रदर्शन

नई दिल्ली,एजेंसी।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई) पर एक बार फिर विमान के उड़ान में देरी के कारण यात्रियों ने हंगामा किया और लगातार हो रही देरी को लेकर वह धरना पर बैठ गए। सोशल मीडिया पर दिल्ली हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट के करीब 200 यात्रियों ने सोमवार से दुबई की उनकी उड़ानों का कई बार समय बदले जाने एवं बहुत ज्यादा देरी होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसकी आलोचना की है। यात्रियों की परेशानी, धरना देने सहित कर्मचारियों के यात्रियों के बहस का भी वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों ने एयरलाइंस से जुड़े अपने खराब अनुभव भी साझा किया।

एक वीडियो में यात्री फर्श पर बैठे हैं जबकि एक अन्य वीडियो में एक कर्मचारी यात्रियों से वीडियो बनाने के लिए मना कर रहा है। धीरे धीरे यात्रियों का वीडियो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी वायरल हो गया और लोगों ने इस पर शिकायत भरे कमेंट किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को दुबई के लिए दो उड़ानें -एसजी 5111 और एसजी 5105 - क्रमशः सुबह और शाम को रवाना होने वाली थीं, लेकिन उनके प्रस्थान का समय बदल दिया गया। ऐसे में कई यात्री हवाई अड्डे पर फंस गए। थोड़ी थोड़ी देर पर उड़ान के समय में परिवर्तन के कारण यात्रियों ने विरोध शुरू कर दिया। लंबे समय से यात्री चेकइन के लिए टर्मिनल तीन पर इंतजार करते रहे।

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि स्पाइसजेट की दुबई जाने वाली दो उड़ानों में 24 घंटे से ज्यादा की देरी होने से यात्रियों का धैर्य जवाब दे रहा है। एक उड़ान को कल सुबह रवाना होना था, लेकिन वह अभी तक उड़ान नहीं भर सकी थी। दूसरी उड़ान कल रात के लिए निर्धारित थी, वह भी एयरपोर्ट पर ही खड़ी रही। बार-बार उड़ान टलने से यात्री परेशान हो गए और उन्होंने टर्मिनल पर विरोध प्रदर्शन किया।

जेएमसी में छात्राओं के लिए हॉस्टल की मांग, केवाईएस ने सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली,एजेंसी।

क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) के प्रतिनिधिमंडल ने जीसस एंड मेरी कॉलेज की छात्राओं के साथ कॉलेज प्राचार्य से मुलाकात कर दिल्ली के बाहर से आने वाली जरूरतमंद छात्राओं के लिए तत्काल छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदर्शन की चेतावनी के बाद प्राचार्य ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मैत्रेयी कॉलेज के प्राचार्य से भी मुलाकात कर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। केवाईएस ने कहा कि सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद संगठन द्वारा छात्रावास सुविधा की मांग को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत दोनों कॉलेजों में यह ज्ञापन दिया गया।

संगठन के अनुसार, छात्रावास की कमी के कारण बाहर से आने वाले विद्यार्थी किराए के कमरों और पेइंग गेस्ट आवासों में रहने को मजबूर हैं। कई बार उन्हें असुरक्षित इमारतों, मकान मालिकों की मनमानी और विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। संगठन ने कॉलेज प्रशासन से इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने और छात्रावास उपलब्ध कराने की योजना पर स्पष्ट बयान जारी करने की मांग की।

केवाईएस ने यह भी दावा किया कि जेएमसी की छात्राओं ने कक्षाओं में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी किए जाने की जानकारी दी है। संगठन ने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा कि वह आने वाले दिनों में कॉलेज प्रशासन के समक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। संगठन ने दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद बाहरी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की मांग को लेकर अभियान तेज करने की बात कही।

15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति मिली

नई दिल्ली,एजेंसी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म की शिकार 15 वर्षीय किशोरी को 30 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी है। अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यौन हिंसा के परिणामस्वरूप हुई गर्भावस्था को जारी रखने के लिए पीड़िता को मजबूर करना और उसकी इच्छा के विरुद्ध मां बनने की जिम्मेदारी डालना सम्मान के साथ जीने के उसके अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा।

अदालत ने कहा कि महिला की शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार में यह निर्णय लेने का अधिकार भी शामिल है कि वह मां बनना चाहती है या नहीं। पीठ ने माना कि यौन उत्पीड़न के कारण गर्भवती हुई पीड़िता को बच्चे को जन्म देने और उसका पालन-पोषण करने के लिए बाध्य करना उसके शारीरिक और मानसिक आघात को और बढ़ा सकता है। मामले को दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक बताते हुए अदालत ने कहा कि किसी महिला के अपने शरीर के संबंध में अधिकार में उसकी प्रजनन संबंधी पसंद भी शामिल है।

अदालत के अनुसार, दुष्कर्म के कारण गर्भधारण करने वाली नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके सम्मान और व्यक्तिगत स्वायत्तता से जुड़े अधिकारों को प्रभावित करेगा। पीठ ने यह भी कहा कि 15 वर्षीय बच्ची को केवल इसलिए मां के रूप में नहीं देखा जा सकता क्योंकि उसे यौन हिंसा के परिणामस्वरूप गर्भावस्था का सामना करना पड़ा है। अदालत ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को जल्द से जल्द गर्भावस्था समाप्त करने की प्रक्रिया की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। अदालत ने पूरी चिकित्सकीय प्रक्रिया का उचित अभिलेख रखने के लिए भी कहा।

साथ ही चिकित्सकों को निर्देश दिया गया कि दुष्कर्म के संबंध में दर्ज आपराधिक मामले की जांच में आवश्यक डीएनए पहचान और अन्य न्यायिक उद्देश्यों के लिए ऊतक अथवा भ्रूण के आवश्यक हिस्से सुरक्षित रखे जाएं। अदालत ने दिल्ली सरकार को गर्भावस्था समाप्त करने से जुड़ा पूरा चिकित्सकीय खर्च उठाने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि चिकित्सकीय प्रक्रिया के बावजूद बच्चा जीवित पैदा होता है तो उसकी जान बचाने और आवश्यक चिकित्सा देखभाल के लिए सभी संभव उपाय किए जाएं। ऐसी स्थिति में बच्चे के संबंध में आगे की कार्रवाई बाल कल्याण समिति द्वारा कानून के अनुसार की जाएगी। पीड़िता ने 30 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। मामले में गर्भावस्था की अवधि अधिक होने के कारण चिकित्सकीय और कानूनी दोनों पहलू महत्वपूर्ण थे। अदालत ने माना कि गर्भावस्था अधिक बढ़ जाने पर चिकित्सकीय प्रक्रिया में अतिरिक्त सावधानी आवश्यक होती है। हालांकि, केवल गर्भावस्था की अवधि अधिक होने के आधार पर किसी नाबालिग को शारीरिक स्वायत्तता, सम्मान और प्रजनन संबंधी निर्णय के अधिकार पर विचार से वंचित नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि यौन हिंसा की पीड़िता को उस घटना के परिणामस्वरूप पैदा होने वाले बच्चे को जन्म देने और उसका पालन-पोषण करने के लिए मजबूर करने से उसे लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है।

'दिल्ली का नाम 'इंद्रप्रस्थ' करने की मांग

नई दिल्ली,एजेंसी।

इंद्रप्रस्थ पुनर्जागरण न्यास ने दिल्ली की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और राष्ट्रीय राजधानी का नाम बदलकर 'इंद्रप्रस्थ' किए जाने की मांग की है। न्यास के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर इस संबंध में गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का प्रमुख केंद्र रही है तथा महाभारत काल से इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जोड़ा जाता है। न्यास ने दिल्ली के प्राचीन इतिहास, हिन्दू शासकों और उनसे जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार को और अधिक महत्व देने की आवश्यकता जताई। न्यास ने पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक बजट के उपयोग की समीक्षा, इंद्रप्रस्थ तथा प्राचीन विरासत से जुड़े स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष योजना है।

जिमखाना क्लब के सदस्यों को हाईकोर्ट जाने की अनुमति

नई दिल्ली,एजेंसी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली जिमखाना क्लब के 11 सदस्यों को दिल्ली हाईकोर्ट जाने की इजाजत दे दी। इन सदस्यों ने केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत क्लब की 27.3 एकड़ जमीन और बिल्डिंग को अपने कब्जे में लेने और उसके बाद खाली कराने की कार्रवाई शुरू की गई थी। इन 11 सदस्यों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को बताया कि अभी क्लब का मैनेजमेंट केंद्र सरकार की बनाई एक कमेटी संभाल रही है और वह सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकती। सिंह ने कहा कि सरकार की बनाई कमेटी ने चुनाव कराने और चुने हुए लोगों को नियंत्रण सौंपने के लिए एनसीएलएटी की तय समय-सीमा से ज्यादा समय ले लिया है।

शाह सभागार में 19 सितंबर को मनेगा हिमाचली सायर उत्सव

नई दिल्ली,एजेंसी।

हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक लोक पर्व सायर उत्सव 19 सितंबर को दिल्ली के राजनिवास मार्ग स्थित गुजराती समाज के शाह सभागार में धूमधाम से मनाया जाएगा। हिमाचल मंडी जनकल्याण सभा की ओर से आयोजित इस वार्षिक समारोह में हिमाचली लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। सभा के अध्यक्ष के.आर. वर्मा ने बताया कि संस्था पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली में सायर उत्सव का आयोजन कर हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत को संजोने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जन्मभूमि से दूर रहकर भी संस्था हिमाचली परंपराओं और लोक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ मंत्री रहे ठाकुर कौल सिंह समारोह में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। सभा के पदाधिकारियों के अनुसार, सायर उत्सव के माध्यम से दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले हिमाचली लोगों को अपनी लोक परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आयोजकों ने कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियां पूरी करने की बात कही है।

अदालत ने स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी

नई दिल्ली,एजेंसी।

पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को खुद को 'इन्फ्लुएंसर' बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। भारद्वाज जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग एक्टिविस्ट के पिता के साथ कथित मारपीट के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह लालर ने भारद्वाज को अंतरिम राहत देने का आदेश दिया। यह घटनाक्रम कोर्ट द्वारा भारद्वाज की रेगुलर जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखने के एक दिन बाद हुआ है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि क्या कथित घटना के समय भारद्वाज ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। अभियोजन पक्ष ने कहा था कि शुरुआती शिकायत में ऐसी किसी भाषा के इस्तेमाल का जिक्र नहीं था और यह आरोप बाद में लगाया गया जब शिकायतकर्ता का बयान दोबारा दर्ज किया गया, जिसके बाद एफआईआर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं जोड़ी गईं।

भारद्वाज के वकील ने जमानत की मांग की थी जबकि अभियोजन पक्ष ने अर्जी का विरोध किया। भारद्वाज पर जुलाई में जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग प्रदर्शनकारी के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट करने का आरोप है। पुलिस ने पहले कहा था कि पीड़ित को लगी चोटें 'मामूली' थीं और कथित तौर पर स्टील के ब्रेसलेट से लगी थीं। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं को शामिल किया गया है। यह घटनाक्रम पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा भारद्वाज की जमानत अर्जी पर समय से पहले सुनवाई करने से इनकार करने और इसे 14 सितंबर के लिए सूचीबद्ध करने के कुछ दिनों बाद हुआ है।

स्वतंत्र भारद्वाज को 4 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हिरासत में लिया गया था, जब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रतिनिधियों ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले भारद्वाज द्वारा कथित मारपीट के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दायर 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस नवीन चावला और रविंदर डुडेजा की बेंच ने याचिका को तब खारिज कर दिया जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि भारद्वाज को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका था।

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेगी डिजीटल लॉकर की सुविधा

नई दिल्ली,एजेंसी।

यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली के चार प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर डिजीटल लॉकर की सुविधा शुरु की गई है। उत्तर रेलवे के इन चार प्रमुख रेलवे स्टेशनों में नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल शामिल हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार वाणिज्यिक पहल के तहत प्रदान की गई यह सुविधा यात्रियों को सामान को अस्थायी रूप से रखने (स्टोरेज) के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और परेशानी मुक्त विकल्प है।

इन लॉकरों में सामान रखने एवं उसे निकालने के लिए ओटीपी का इस्तेमाल होगा। इससे यात्री अपनी प्रतीक्षा अवधि या स्टेशन से बाहर भ्रमण के दौरान भारी सामान उठाए बिना अपना सामान सुरक्षित रूप से रख और वापस निकाल सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से पर्यटकों, ट्रेनों के बीच लंबी प्रतीक्षा अवधि वाले यात्रियों और भारी सामान के साथ यात्रा करने वालों के लिए उपयोगी होगी। यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चारों रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न आकारों (मिनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज) के लॉकर उपलब्ध कराए गए हैं। यात्री अपने सामान के आकार के अनुसार लॉकर का चयन कर सकते हैं।

नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर सुविधा चालू कर दी गई है और दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल में इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, डिजिटल लगेज लॉकर सुविधा प्लेटफॉर्म नंबर 16 के पास, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के नीचे मेन हॉल में उपलब्ध है।

प्रिंटर देखने के बहाने घर में घुसे हमलावर, महिला पर छह गोलियां बरसाईं

नई दिल्ली,एजेंसी।

पश्चिमी दिल्ली के नंगली एक्सटेंशन में पत्नी की हत्या की साजिश रचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि सरकारी विद्यालय में शिक्षक पति ने पत्नी की हत्या के लिए अपने बचपन के दोस्त को 3.5 लाख रुपये की सुपारी दी। साजिश के तहत दो हमलावर प्रिंटर देखने के बहाने महिला के घर में दाखिल हुए और करीब 40 मिनट बाद उस पर 6 गोलियां चला दीं। हमले में महिला को 3 गोलियां लगीं। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बच गई।

पुलिस ने मामले में मंगलवार को दोनों हमलावरों दीपक और आकाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, घायल महिला के पति संदीप को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। साजिश में कथित रूप से शामिल उसका बचपन का दोस्त अरविंद अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस के अनुसार, वारदात रविवार सुबह करीब 6 बजे नंगली एक्सटेंशन की गली नंबर-1 में हुई। संदीप ने कथित तौर पर पहले अपनी पत्नी संध्या से कहा था कि घर पर 2 लोग प्रिंटर देखने के लिए आएंगे।

कुछ देर बाद दीपक और आकाश वहां पहुंचे और प्रिंटर की जांच करने की बात कहकर घर के भीतर प्रवेश कर गए। दोनों करीब 40 मिनट तक घर के अंदर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रिंटर खोलकर उसकी जांच करने का बहाना किया। जब संध्या उनके लिए पानी लेकर पहुंची, तभी दोनों ने अचानक उस पर गोलियां चला दीं। हमलावरों ने संध्या पर कुल 6 गोलियां चलाईं, जिनमें से 3 गोलियां उसे लगीं। गोली लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस दल तत्काल मौके पर पहुंचा और घायल संध्या को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने समय पर उपचार शुरू किया, जिसके कारण उसकी जान बच गई। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने हमलावरों की पहचान की और मंगलवार को दीपक तथा आकाश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कथित तौर पर सामने आया कि संदीप ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए अपने बचपन के दोस्त अरविंद को 3.5 लाख रुपये की सुपारी दी थी।

पुलिस के अनुसार, इसके बाद अरविंद ने अपने भाई दीपक और उसके साथी आकाश को वारदात को अंजाम देने के लिए भेजा। पुलिस अब संदीप, अरविंद और दोनों हमलावरों के बीच हुई बातचीत, सुपारी की रकम के लेनदेन तथा पूरी साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक, संदीप और संध्या की शादी करीब 3 वर्ष पहले हुई थी।

वेतन बढ़ोतरी, मेडिकल सुविधा की मांग के लिए बस ड्राइवरों ने की हड़ताल

नई दिल्ली,एजेंसी।

डीटीसी और परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसों के ड्राइवरों ने मंगलवार सुबह हड़ताल कर दी। वेतन बढ़ोतरी, मेडिकल सुविधा, सालाना बोनस और ओवर टाइम का भुगतान समेत कई मुद्दों को लेकर ड्राइवर काम बंद कर सड़कों पर उतर आए। बुराड़ी, दिलशाद गार्डन, केशोपुर, ग्रेटर कैलाश, झिलमिल समेत अधिकांश डिपो में हड़ताल हो जाने और बसों के सड़कों पर न निकलने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें मेट्रो, ऑटो और अन्य वैकल्पिक परिवहन साधनों से यात्रा करनी पड़ी।

ड्राइवरों का कहना है कि 10-15 साल का अनुभव होने के बावजूद उन्हें अकुशल श्रमिकों की तरह दैनिक वेतन दिया जा रहा है। उन्हें प्रतिदिन 862 रुपये वेतन दिया जा रहा है, जबकि इसी काम के लिए डीटीसी के स्थायी ड्राइवरों को 50-60 हजार से ज्यादा वेतन दिया जा रहा है। उनका कहना है कि इन बसों के ड्राइवरों को न तो मेडिकल सुविधा दी जा रही है और न ही ओवर टाइम का भुगतान किया जा रहा है। 8 घंटे की बजाय 10 से 11 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों ने अपनी मांगों को लेकर बस ऑपरेटर्स और डिपो के अधिकारियों से कई बार वार्ता की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मंगलवार से हड़ताल का फैसला लिया गया।

दिल्ली के कुछ डिपो में सुबह की शिफ्ट में ड्राइवर बसों को लेकर निकल गए थे, लेकिन दोपहर तक सभी डिपो में हड़ताल का संदेश पहुंच गया। हड़ताली ड्राइवरों ने अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित हो रहीं बसों को भी रुकवा दिया। इसके चलते बुराड़ी, मयूर विहार फेज-3 समेत कई इलाकों में सड़कों पर ही बसों की कतारें लग गईं। यात्रियों को बीच सफर में बसों से उतरकर पैदल आगे जाना पड़ा। इसकी वजह से मंगलवार सुबह नौकरीपेशा लोग ड्यूटी पर पहुंचने में लेट हो गए।

ड्राइवरों का कहना है कि अब हड़ताल कर दी है तो तब तक जारी रहेगी, जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी। उनका कहना है कि वे खुद भी यात्रियों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बस ऑपरेटर्स और सरकार मिलकर ड्राइवरों का शोषण कर रहे हैं।

RNI.No DLHIN/25/A2841

स्वामी, प्रकाशक, संपादक देवेंद्र सिंह तोमर एवं मुद्रक रवि भारद्वाज मै. मारुती नंदन प्रिंटर्स एवं पब्लिशर, शक्ति कॉम्प्लेक्स 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110042 से मुद्रित एवं हॉउस नंबर 16/ 9980, गली नंबर-5, सराय रोहिल्ला न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।

संपादकीय कार्यालय - B4/265B केशव पुरम नई दिल्ली -110005। फोन-011-40106508
मोबाइल-9911466900/ 8076353913। Email.saahassamachardainik@gmail.com

संपादक देवेंद्र सिंह तोमर

इस अंक में प्रकाशित खबरों एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा नई दिल्ली के न्यायालय में होगा।

किशाऊ परियोजना से दिल्ली को मिलेगा अतिरिक्त पानी: रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौते से दिल्ली को 109.9 मिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी मिल सकेगा, जिससे पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली कैबिनेट ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर हुए महत्वपूर्ण समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल का आभार जताया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस परियोजना को वर्षों से लंबित विषय का समाधान बताते हुए केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के सहयोग की सराहना की गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौते से दिल्ली को 109.9 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) अतिरिक्त पानी मिल सकेगा, जिससे राजधानी की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और यमुना में पर्यावरण के लिए जरूरी जलप्रवाह भी बेहतर होगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पानी की कमी दिल्ली की बड़ी चुनौतियों में से एक है और किशाऊ परियोजना के आगे बढ़ने से राजधानी की जल सुरक्षा मजबूत होगी तथा कम पानी वाले समय में अतिरिक्त कच्चा पानी उपलब्ध होने से पेयजल आपूर्ति को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को भी सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि किशाऊ परियोजना ऊपरी यमुना बेसिन की महत्वपूर्ण जल भंडारण परियोजनाओं में से एक है। टौंस नदी पर बनने वाली इस परियोजना में लगभग 1,324 एमसीएम उपयोगी जल भंडारण की क्षमता होगी। मानसून के दौरान उपलब्ध पानी का भंडारण कर जरूरत के अनुसार नियंत्रित तरीके से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

इससे दिल्ली की भविष्य की जल जरूरतों को दीर्घकालिक आधार मिलेगा तथा भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण के प्रयासों को भी बल मिलेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यमुना नदी में आवश्यक जलप्रवाह को बेहतर करना भी है। पर्याप्त जलप्रवाह नदी के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। दिल्ली सरकार यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। ऐसे में किशाऊ परियोजना से मिलने वाला लाभ यमुना पुनर्जीवन के प्रयासों को भी मजबूती प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पेयजल और सिंचाई के साथ-साथ जलविद्युत उत्पादन तथा यमुना में पर्यावरणीय जलप्रवाह बेहतर करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

किशाऊ परियोजना को लेकर 6 राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद इसके आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है। जून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में परियोजना को लेकर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनी थी। अब इस सहमति को समझौते के रूप में औपचारिक रूप दिया गया है। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस परियोजना से राजधानी की वर्तमान और भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। साथ ही यमुना के पर्यावरणीय प्रवाह में सुधार होने से नदी के पुनर्जीवन और संरक्षण के प्रयासों को भी अपेक्षित आधार मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ परियोजना का महत्व केवल पेयजल आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यमुना के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर्याप्त जलप्रवाह से नदी के पुनर्जीवन और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि परियोजना पेयजल, सिंचाई और जलविद्युत उत्पादन के साथ-साथ यमुना में आवश्यक जलप्रवाह सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी अहम है। छह राज्यों के बीच बनी सहमति से वर्षों से लंबित परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।

बात मुद्दे की

आलोक गौड़

कानून खत्म हो गया, लेकिन 'अपराधी' कौन है?

नई दिल्ली। किसी इंसान को अपराधी मानने के लिए उसका अपराध करना जरूरी है या सिर्फ उसकी जाति जान लेना काफी है? अगर यह सवाल आपको असहज करता है तो ऐसा होना स्वाभाविक ही है। क्योंकि हमारे देश में कभी एक कानून ऐसा था, जो किसी व्यक्ति के कर्म नहीं बल्कि उसके जन्म को अपराध का आधार मानता था। अंग्रेजों ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया और कई घुमंतू, अर्ध-घुमंतू और पारंपरिक पेशे से जुड़े समुदायों को सामूहिक रूप से 'जन्मजात अपराधी' करार करदिया था। आज उस कानून को खत्म हुए 74 साल हो चुके हैं। 31 अगस्त 1952 को कानून रद्द हुआ था और यह समुदाय 'विमुक्त' घोषित किए गए। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या कानून के साथ वह सोच भी खत्म हो गई, जिसने लाखों लोगों को जन्म से संदिग्ध बना दिया था? अगर जवाब हां है तो फिर आज भी इन समुदायों से यह शिकायत क्यों सुनाई देती है कि अपराध होने पर शक की पहली निगाह उन्हीं पर जाती है? चोरी हो, बच्चा गायब हो या कोई दूसरी आपराधिक घटना के बाद क्या पुलिस और समाज कभी-कभी अपराधी की तलाश करने से पहले किसी खास समुदाय को तलाशने नहीं लगते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर 1952 में आखिर बदला क्या?

कानून बदला, लेकिन क्या सामाजिक भी नजरिया बदला? यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी विडंबना है। देश आजाद हुआ, संविधान आया, नागरिकों को समानता और मौलिक अधिकार मिले। लेकिन जिन लोगों को अंग्रेजों ने सामूहिक अपराधी घोषित किया था, उनकी अगली पीढ़ियां आज भी स्थायी पहचान, घर, शिक्षा, रोजगार और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं।

सरकारें कह सकती हैं कि हमने ऐसे लोगों के लिए योजनाएं बनाई हैं। बोर्ड बनाए गए हैं। आर्थिक सशक्तीकरण के कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाणपत्र चाहिए, स्थायी पता चाहिए, बैंक खाता चाहिए और तरह-तरह के दस्तावेज चाहिए। जिस समुदाय का इतिहास ही घुमंतू रहा हो, उसके लिए सबसे बड़ी सरकारी शर्त ही अगर 'स्थायी पता' हो तो फिर यह व्यवस्था किसके लिए बनाई गई है? क्या यह गरीबों की मदद करने वाली व्यवस्था है या पहले कागजों में नागरिक साबित होने की परीक्षा लेने वाली व्यवस्था? एक और गंभीर समस्या आंकड़ों की है। जब किसी समुदाय की सही संख्या ही मालूम न हो तो उसकी समस्याओं की सही तस्वीर कैसे बनेगी? देश में जातिगत जनगणना का आखिरी व्यापक आंकड़ा 1931 का है। इतने लंबे अंतराल के बाद भी अगर कोई समुदाय अपनी आबादी और सामाजिक स्थिति के भरोसेमंद आंकड़ों के लिए संघर्ष कर रहा है तो इसे सिर्फ प्रशासनिक कमी कहकर टाला नहीं जा सकता।

जिसकी गिनती नहीं होगी, उसके हिस्से का बजट कौन मांगेगा? और यह मामला केवल गरीबी का भी नहीं है। गरीबी से लड़ने के लिए रोजगार और आर्थिक सहायता जरूरी है, लेकिन ऐतिहासिक कलंक से लड़ने के लिए समाज की मानसिकता बदलनी होगी।

एक बच्चे ने अपराध नहीं किया। फिर भी अगर उसके उपनाम या जाति से उसके चरित्र पर शक होने लगे तो उसके लिए संविधान की समानता कितनी वास्तविक है? यही कारण है कि 31 अगस्त 2026 को जब इस कानून के खत्म होने के 75 साल पूरे हुए, तब केवल समारोह करना पर्याप्त नहीं था। सरकार को यह बताना चाहिए कि इन समुदायों की वास्तविक आबादी कितनी है, कितने परिवारों के पास स्थायी आवास नहीं है, कितने बच्चों की शिक्षा बीच में छूटती है, कितने लोग दस्तावेजों के अभाव में योजनाओं से बाहर रह जाते हैं और पुलिस-न्याय व्यवस्था में इनके साथ व्यवहार की वास्तविक स्थिति क्या है। और समाज को भी अपने हिस्से का सवाल सुनना होगा।

हमने अंग्रेजों का वह कानून तो हटा दिया जिसने इन्हें 'जन्मजात अपराधी' कहा था। लेकिन क्या हमने अपने मन से भी यह शब्द मिटाया है? अगर किसी समुदाय को अपराध की हर घटना के बाद संदेह की निगाह से देखा जाता है, तो यह केवल उस समुदाय का अपमान नहीं है। यह संविधान की उस बुनियादी धारणा पर सवाल है कि नागरिक की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके अधिकारों और कानून के सामने उसकी बराबरी से होती है।

विमुक्त जनजातियों को दया नहीं चाहिए। उन्हें कोई विशेष एहसान भी नहीं चाहिए। उन्हें वही चाहिए जिसका वादा संविधान हर नागरिक से करता है कि पहचान, सम्मान, अवसर, सुरक्षा और न्याय।

कानून ने 1952 में उन्हें 'विमुक्त' कर दिया था।

अब 2026 में सवाल सरकार से कम और समाज से ज्यादा है कि क्या हम उन्हें सचमुच मुक्त नागरिक मान चुके हैं, या हमारे दिमाग में आज भी 1871 का वह कानून जिंदा है?

क्योंकि किसी कानून को खत्म करना आसान है।

किसी इंसान के माथे से सदियों पुराना कलंक मिटाना ही असली आजादी है।

उपराज्यपाल ने की जेजे क्लस्टर पुनर्वास पहलों की समीक्षा

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मंगलवार को 'दिल्ली स्लम एवं जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026' के तहत बेहतर आवास और रहने की स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जेजे क्लस्टर पुनर्वास पहलों की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सभी के लिए सम्मानजनक आवास' के विजन और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के अनुरूप, यह नीति कट-ऑफ तारीख को एक जनवरी 2025 तक बढ़ाकर कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाती है। इसमें मौजूदा जगह पर पुनर्विकास, जरूरी नागरिक बुनियादी ढांचे और वैकल्पिक आवास को प्राथमिकता दी गई है।

उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निवासियों के संपर्क में रहने, उनकी चिंताओं को सुनने और समस्याओं का तेजी से समाधान करने के निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि निवासियों को जमीनी स्तर पर बदलाव दिखना चाहिए। हर परिवार एक सुरक्षित, सम्मानजनक घर और बेहतर जीवन-स्तर का हकदार है। विकसित दिल्ली के निर्माण के दौरान कोई भी पात्र परिवार पीछे नहीं छूटना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जून में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की 36वीं बोर्ड बैठक में झुग्गी पुनर्वास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया।

बैठक में तय किया गया कि दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक स्थापित सभी पात्र झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास का लाभ दिया जाएगा। राजधानी की जेजे बस्तियों में रहने वाले लगभग 4 से 5 लाख परिवारों यानी करीब 20 लाख लोगों के लिए पक्के और सम्मानजनक आवास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। लंबे समय से पुरानी पात्रता तिथि के कारण बड़ी संख्या में परिवार पुनर्वास के लाभ से वंचित रह जाते थे।

नई कट-ऑफ तिथि तय होने से अब अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा। इन कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों के खेलने के मैदान और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नई नीति में पारिवारिक विस्तार की वास्तविक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

पुरानी सोसायटियों के पुनर्विकास की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो प्रणाली की मांग

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली में पुरानी और जर्जर ग्रुप हाउसिंग सोसायतियों के पुनर्विकास का रास्ता आसान बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आरडब्ल्यूए और कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायतियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श बैठक की। प्रतिनिधियों ने एफएआर बढ़ाने और कई एजेंसियों से मंजूरी के लिए सिंगल विंडो प्रणाली की मांग रखी। पुराने भवनों की सुरक्षा जांच के लिए संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराने का सुझाव भी दिया। वहीं, उद्योग को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र को डीडीए की जमीन उपलब्ध कराने सहित अन्य प्रावधानों पर औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए।

उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर दिल्ली मास्टर प्लान दिल्ली-2047 को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अलग-अलग वर्गों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। डीडीए अधिकारियों ने एक बैठक में आरडब्ल्यूए और कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायतियों के प्रतिनिधियों को पुरानी आवासीय सोसायतियों के पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित नीति और नियोजन प्रावधानों की जानकारी दी। इसमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी), पुनर्विकास के लिए प्रोत्साहन एफएआर, खुले स्थान, सड़क नेटवर्क, पार्किंग, सतत विकास और कचरा प्रबंधन पर चर्चा की। डीडीए ने बताया कि पुनर्विकास का उद्देश्य अधिक आवासीय इकाइयों के साथ बेहतर खुले स्थान और पार्किंग उपलब्ध कराना है, जिससे सुरक्षित आवासीय वातावरण तैयार हो।

वहीं, दूसरी बैठक में सीआईआई, फिक्की, पीएचडी चैंबर, एसोचैम और डीएसआईआईडीसी के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें उद्योग को बढ़ावा देने, डीडीए की भूमि निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराने और संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (आईएसआर) की रूपरेखा पर चर्चा हुई। डीडीए ने इनके सवालों और समस्याओं का समाधान करते हुए विभिन्न प्रावधानों पर जवाब दिया।

तीन स्कूलों को मिली बम की धमकी

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली में मंगलवार को तीन स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद विद्यार्थियों को बाहर निकाला गया तथा सुरक्षा जांच की गई। धमकी बाद में झूठी साबित हुई, क्योंकि स्कूलों की तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिन स्कूलों को धमकी मिली, उनमें चाणक्यपुरी स्थित ब्रिटिश स्कूल, धौला कुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल और लोदी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय है। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अनुसार, उसके पास सुबह साढ़े 11 बजे धौला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल से फोन आया जिसके बाद एक अग्निशमन गाड़ी मौके पर भेजी गई।

डीएफएस अधिकारी ने कहा कि सघन तलाशी के बाद एक बजकर पांच मिनट पर बम की धमकी फर्जी घोषित की गई। पुलिस को ब्रिटिश स्कूल में भी बम की धमकी वाले ईमेल के बारे में सूचना मिली। जांच के बाद इसे भी झूठी खबर करार दिया गया। पुलिस के मुताबिक, सुरक्षा कर्मियों ने किसी भी संदिग्ध वस्तु या सामान को लेकर इन स्कूलों के भवनों और आस-पास के इलाकों की तलाशी की। पुलिस जांच के तहत ईमेल के स्रोत का पता लगा रही है और धमकी से जुड़ी जानकारी का भी विश्लेषण कर रही है। एक अधिकारी ने कहा कि तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला तथा सुरक्षा एजेंसियों के निरीक्षण के बाद यह धमकी झूठी साबित हुई। सरदार पटेल विद्यालय ने एक नोटिस में कहा कि सुरक्षा संबंधी धमकी मिलने के बाद सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया।

डूसू चुनाव में एनएसयूआई की जीत का दावा, देवेन्द्र ने पैनल को जिताने की अपील की

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के पैनल को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को होने वाले चुनाव में छात्र मौजूदा शिक्षा नीति और भाजपा सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने छात्रों से एनएसयूआई के पैनल 6-4-1-2 को जिताने की अपील करते हुए कहा कि इससे देशभर में बदलाव का संदेश जाएगा और छात्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे राहुल गांधी के हाथ मजबूत होंगे।

देवेन्द्र यादव ने नजफगढ़, चांदनी चौक और नई दिल्ली जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठकों को संबोधित किया। इन बैठकों का आयोजन संबंधित जिला अध्यक्षों मोहम्मद उस्मान, महेन्द्र मंगला और राजेश यादव की ओर से किया गया। बैठकों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, एनएसयूआई और डूसू के पूर्व पदाधिकारियों, पूर्व विधायकों, जिला एवं प्रखंड पदाधिकारियों तथा विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। देवेन्द्र यादव ने कहा कि एनएसयूआई से जुड़े छात्र प्रत्येक महाविद्यालय में अधिक से अधिक विद्यार्थियों से संपर्क करें और उन्हें मौजूदा शिक्षा नीति से जुड़ी समस्याओं तथा भाजपा सरकार की नीतियों के कारण छात्रों के सामने पैदा हुई चुनौतियों से अवगत कराएं।

उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी की ओर से छात्रों के अधिकारों को लेकर चलाए जा रहे 'छात्रों की गूंज' अभियान के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी देने की अपील की। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को चुनाव के अंतिम चरण में पूरी ताकत के साथ छात्रों तक पहुंचना चाहिए, ताकि संगठन का पैनल डूसू चुनाव में एकतरफा जीत हासिल कर सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को चुनाव जिताने के लिए हर तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आशंका जताई कि भाजपा कथित तौर पर डूसू चुनाव में भी मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है।

देवेन्द्र यादव ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से ऐसी किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान पूरी सक्रियता के साथ काम करना होगा और छात्रों के मतदान के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में देश के विभिन्न हिस्सों से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं।

प्रेम, करुणा और मानव एकता के संदेश के साथ 30वें विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन का आगाज

कृपाल बाग में देश-विदेश के धर्मगुरु एक मंच पर जुटे, संत राजिन्दर सिंह जी महाराज ने किया उद्घाटन; नेत्र शिविर में 1,987 मरीजों की जांच

नई दिल्ली, साहस समाचार।

राजधानी दिल्ली में विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं के संतों एवं धर्मगुरुओं का आठ दिवसीय समागम शुरू हो गया है। सावन कृपाल रूहानी मिशन के प्रमुख संत राजिन्दर सिंह जी महाराज ने 13 सितंबर को कृपाल बाग में 30वें विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में शांति, आध्यात्मिकता, प्रेम, करुणा और मानवीय एकता जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। आयोजकों के अनुसार, देशभर से 50 हजार से अधिक लोगों और 150 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है।

उद्घाटन समारोह में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए संत राजिन्दर सिंह जी महाराज ने ईश्वरीय प्रेम और करुणा को मानव जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता व्यक्ति को अपने भीतर मौजूद प्रेम और प्रकाश का अनुभव कराने के साथ उसे मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने लोगों से आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आत्मिक विकास और मानवीय मूल्यों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। सम्मेलन के पहले दिन आध्यात्मिक 'तरही मुशायरे' का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत माता रीटा जी ने सूफी-संत एवं शायर संत दर्शन सिंह जी महाराज की रचना पर आधारित गजल के गायन से की। इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों से आए उर्दू शायरों ने प्रेम और आध्यात्मिकता पर केंद्रित रचनाएं प्रस्तुत कीं।

संत दर्शन सिंह जी महाराज का 105वां प्रकाश दिवस

14 सितंबर को संत दर्शन सिंह जी महाराज का 105वां प्रकाश दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 'दर्शन—असीम प्रेम और करुणा के सागर' विषय पर सेमिनार हुआ। संत राजिन्दर सिंह जी महाराज ने संत दर्शन सिंह जी महाराज के जीवन और शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए उन्हें प्रेम, करुणा और दयालुता का प्रतीक बताया।

उन्होंने कहा कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ईश्वरीय प्रेम के माध्यम से मानवता को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। उनकी कविताओं और शिक्षाओं ने लोगों को जीवन के उद्देश्य—स्वयं को जानने और ईश्वर को पाने—की ओर प्रेरित किया।

संत राजिन्दर सिंह जी महाराज ने कहा कि मनुष्य के भीतर ईश्वर का प्रेम और प्रकाश मौजूद है तथा ध्यान-अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा कर सकता है। कार्यक्रम का समापन प्रार्थना के साथ हुआ।

धर्मगुरुओं ने प्रेम और सेवा को बताया साझा सूत्र

सम्मेलन में हरिद्वार के डॉ. स्वामी प्रेमानंद जी, ऋषिकेश के महंत श्री रवि प्रपन्नाचार्य जी, इलाहाबाद के जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य स्वामी दिलीप योगीराज जी और दिल्ली के डॉ. फादर नॉर्बर्ट हरमन समेत विभिन्न धर्मगुरुओं ने अपने विचार रखे।

वक्ताओं ने कहा कि सच्चा आध्यात्मिक प्रेम जाति, धर्म और समुदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता को जोड़ता है। स्वामी दिलीप योगीराज जी ने गुरु के प्रेम की तुलना नदी से करते हुए कहा कि यह मनुष्य के भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों को दूर करने में मदद करता है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों अमेरिका के जोनाथन क्रूगर और ऑस्ट्रिया की मार्गरेट जर्नी ने भी संत दर्शन सिंह जी महाराज से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।

एनसीआर में प्रदूषण मानकों के उल्लंघन पर 25 डीजल जनरेटर सील होंगे

नई दिल्ली,साहस समाचार।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण नियंत्रण मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई तेज करते हुए 25 डीजल जनरेटर (डीजी) सेट सील करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा तीन निर्माण एवं विध्वंस परियोजनाओं और एक औद्योगिक इकाई को बंद करने की कार्रवाई प्रस्तावित है। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की प्रवर्तन कार्यबल (ईटीएफ) की 139वीं बैठक में लिया गया। बैठक में 24 अगस्त से सात सितंबर तक 15 दिनों में हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई।

इस दौरान एनसीआर में 150 निरीक्षण किए गए। इनमें निर्माण एवं विध्वंस स्थलों के सात, औद्योगिक क्षेत्र के 98 और डीजी सेट से जुड़े 45 निरीक्षण शामिल हैं। हरियाणा के नूंह में तीन सितंबर को विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड की आठ टीमों ने जिला प्रशासन, पुलिस और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ 35 परिसरों का निरीक्षण किया। इनमें 13 मानकों के अनुरूप मिले, जबकि सात इकाइयां बंद मिलीं। इनकी दोबारा जांच की जाएगी। छह मामलों में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने और एक डीजी सेट सील करने की सिफारिश की गई है।

आयोग के अनुसार, अब तक एनसीआर में 28,547 इकाइयों, परियोजनाओं और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा चुका है। इनमें 1,829 बंदी आदेश जारी हुए, जबकि अनुपालन की जांच के बाद 1,479 को दोबारा संचालन की अनुमति दी गई। 126 मामले संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजे गए हैं। 224 मामले अभी दोबारा संचालन की अनुमति देने के लिए जांच के अधीन हैं।

संपादकीय

जिसे जनता ने चुना, वह जनता से दूर क्यों हो गया?

देवेंद्र सिंह तोमर

लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है। वही मतदान करती है, वही प्रतिनिधि चुनती है और वही किसी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। चुनाव के समय यही जनता नेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके घर तक पहुंचा जाता है, हाथ जोड़े जाते हैं, समस्याएं सुनी जाती हैं, वादे किए जाते हैं और भरोसा दिलाया जाता है कि जीतने के बाद हर हाल में जनता के बीच रहेंगे। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद तस्वीर कितनी बदल जाती है, यह किसी से छिपा नहीं है। सवाल सीधा है जिसे जनता ने चुना, वह जनता से दूर क्यों हो गया?

चुनाव के पहले नेता जनता के दरवाजे पर होता है और चुनाव के बाद जनता को नेता के दरवाजे तक पहुंचने के लिए कई दरवाजे पार करने पड़ते हैं। पहले फोन उठता था, अब फोन मिलना मुश्किल है। पहले शिकायत सीधे सुनी जाती थी, अब शिकायत के लिए आवेदन, सिफारिश और कई बार पहचान जरूरी हो जाती है। आखिर लोकतंत्र की यह दूरी पैदा कैसे हुई? क्या जनप्रतिनिधि बनने का अर्थ केवल विधानसभा या संसद में बैठना है? क्या जनता की जिम्मेदारी केवल वोट डालने तक सीमित है? जनता ने प्रतिनिधि को केवल इसलिए नहीं चुना कि वह सदन में उसकी ओर से हाथ उठाए। जनता ने उसे इसलिए चुना कि वह उसकी आवाज बने। उसके मोहल्ले की सड़क, गांव का रास्ता, पानी की समस्या, अस्पताल की व्यवस्था, स्कूल की हालत, रोजगार और सुरक्षा जैसे सवालों को सत्ता के सामने रखे। लेकिन धीरे-धीरे राजनीति में एक अजीब बदलाव आया है। चुनाव जीतने के बाद कई प्रतिनिधियों के आसपास एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हो जाती है, जिसमें आम आदमी की सीधी पहुंच कम होती चली जाती है। नेता और जनता के बीच कार्यकर्ताओं, सहायकों, निजी स्टाफ और सिफारिशों की दीवार खड़ी हो जाती है। यही दीवार लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस जनता ने अपने वोट से किसी को ताकत दी, वही जनता बाद में अपनी छोटी-सी समस्या लेकर भटकती दिखाई देती है। किसी सरकारी कार्यालय में काम अटका है तो जनप्रतिनिधि से उम्मीद की जाती है। अधिकारी सुन नहीं रहा तो नेता से गुहार लगाई जाती है। सड़क नहीं बनी, नाली बंद है, अस्पताल में सुविधा नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं हैं हर समस्या के समाधान की उम्मीद आखिरकार उसी प्रतिनिधि से होती है जिसे जनता ने चुना है। लेकिन जब जनता को जवाब नहीं मिलता तो उसके भीतर निराशा पैदा होती है।

यह कहना गलत होगा कि सभी जनप्रतिनिधि जनता से दूर हो गए हैं। आज भी ऐसे अनेक नेता हैं जो लगातार लोगों के बीच रहते हैं, समस्याएं सुनते हैं और अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं। लेकिन सवाल उन लोगों से है जिनके लिए जनता चुनाव के बाद केवल आंकड़ा बन जाती है। पांच साल में एक बार वोट मांगने वाली राजनीति लोकतंत्र की भावना नहीं हो सकती। जनता को यह भी समझना होगा कि उसकी जिम्मेदारी केवल चुनाव के दिन मतदान करने तक खत्म नहीं होती। जिस तरह जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, उसी तरह जनता को भी अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। उसने क्षेत्र के लिए क्या किया? कितने वादे पूरे हुए? कौन से मुद्दे सदन में उठाए? विकास के लिए कितना प्रयास किया? सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? इन सवालों से लोकतंत्र मजबूत होगा। दुर्भाग्य से हमारे यहां सवाल पूछने को कई बार विरोध समझ लिया जाता है। यदि कोई नागरिक अपने प्रतिनिधि से काम का हिसाब मांगता है तो उसे राजनीतिक विरोधी मान लिया जाता है। यह सोच लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जनप्रतिनिधि जनता का सेवक है, मालिक नहीं।

राजनीति में सबसे बड़ा संकट शायद यही है कि चुनाव जीतने के बाद कई लोग यह भूल जाते हैं कि उनकी कुर्सी उनकी अपनी नहीं है। वह जनता के विश्वास से मिली है। वह विश्वास पांच साल के लिए खाली चेक नहीं है।

पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता: विस्तार या रणनीतिक जोखिम?

ज्योतिर्मय राय

पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता पर भारत की स्थिति स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण होगी। भारत और पाकिस्तान के संबंध दशकों से आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और अन्य रणनीतिक विवादों से प्रभावित रहे हैं। भारत लगातार सीमा-पार आतंकवाद और आतंकवादी ढाँचे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग करता रहा है।

किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन की ताकत केवल उसके सदस्यों की संख्या से नहीं मापी जाती। असली ताकत इस बात से तय होती है कि अलग-अलग हितों वाले देश साझा मुद्दों पर कितनी दूर तक साथ चल सकते हैं। यही कसौटी आज ब्रिक्स के सामने है। पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता की आकांक्षा इसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ब्रिक्समें एक और देश शामिल होगा या नहीं। बड़ा सवाल यह है किक्या विस्तार के साथ संगठन अपनी निर्णय क्षमता, राजनीतिक विश्वसनीयता और साझा एजेंडे की दिशा को बनाए रख पाएगा?

यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण एशिया पहले ही इसका एक उदाहरण देख चुका है। सार्क के पास भौगोलिक निकटता, विशाल बाजार, युवा आबादी और आर्थिक सहयोग की पर्याप्त संभावनाएँ थीं। फिर भी भारत-पाकिस्तान तनाव ने उसके कामकाज को लंबे समय तक प्रभावित किया। ब्रिक्सके सामने चुनौती यह है कि वह ऐसी स्थिति को दोहराने से कैसे बचे। नई दिल्ली में आयोजित 18वां ब्रिक्सशिखर सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक राजनीति गहरे बदलाव के दौर से गुजर रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में अस्थिरता, अमेरिका-चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बदलाव ने दुनिया की पुरानी शक्ति-समीकरणों को चुनौती दी है।

इसी बदलते माहौल में ब्रिक्स का महत्व तेजी से बढ़ा है। संगठन अब केवल उभरती अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक मंच नहीं है। विकास वित्त, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार और आतंकवाद जैसे मुद्दे भी उसके एजेंडे में जगह बना चुके हैं। ऐसे में नए सदस्य का चयन केवल संख्या बढ़ाने का निर्णय नहीं हो सकता। यह संगठन की दिशा और भविष्य की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है।

पाकिस्तान ने नवंबर 2023 में ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया था। इस प्रयास के पीछे उसकी आर्थिक जरूरत और कूटनीतिक महत्वाकांक्षा दोनों दिखाई देती हैं।

आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान लंबे समय से वित्तीय दबाव, विदेशी मुद्रा संकट और बाहरी सहायता पर निर्भरता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में ब्रिक्ससे जुड़ाव उसके लिए बड़े बाजारों, निवेश और विकास वित्त तक संभावित पहुँच का रास्ता खोल सकता है। लेकिन मामला केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है।

ब्रिक्स ग्लोबल साउथ की राजनीति में लगातार महत्वपूर्ण मंच बन रहा है। पाकिस्तान के लिए इसकी सदस्यता का अर्थ होगा कि उसे उन देशों के साथ एक ही मंच पर बैठने का अवसर मिलेगा, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को अधिक बहुध्रुवीय बनाने की वकालत करते हैं।

इसलिए इस सदस्यता को पाकिस्तान अपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिति मजबूत करने के अवसर के रूप में देख सकता है। लेकिन ब्रिक्सके लिए सवाल उलटा है—पाकिस्तान संगठन को क्या देगा? यही वह बिंदु है जहाँ सदस्यता की राजनीतिक और रणनीतिक कसौटी शुरू होती है।

पाकिस्तान की ब्रिक्ससदस्यता पर भारत की स्थिति स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण होगी। भारत और पाकिस्तान के संबंध दशकों से आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और अन्य रणनीतिक विवादों से प्रभावित रहे हैं। भारत लगातार सीमा-पार आतंकवाद और आतंकवादी ढाँचे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग करता रहा है। इसलिए नई दिल्ली के लिए पाकिस्तान की सदस्यता को केवल आर्थिक सहयोग के नजरिए से देखना संभव नहीं होगा। भारत की चिंता का व्यापक आधार यह है कि आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में दोहरे मानदंड स्वीकार नहीं किए जा सकते। यदि किसी देश के साथ रणनीतिक या राजनीतिक सुविधा के कारण अलग व्यवहार किया जाता है, तो बहुपक्षीय सुरक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता कमजोर होती है। ब्रिक्स के भीतर आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक रुख और पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा ने इस मुद्दे को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है।

भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को मजबूती से रखते हुए ब्रिक्सको भारत-पाकिस्तान विवाद का मंच बनने से भी रोके। यही संतुलन भविष्य में नई दिल्ली की कूटनीति की असली परीक्षा होगा। पाकिस्तान की ब्रिक्सआकांक्षा में चीन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। CPEC और दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी पहले से मौजूद है। पाकिस्तान का ब्रिक्समें प्रवेश चीन को दक्षिण एशिया में एक और करीबी साझेदार दे सकता है। लेकिन इसे चीन की सीधी रणनीतिक जीत मानना भी सही नहीं होगा। ब्रिक्स किसी एक देश के नियंत्रण वाला संगठन नहीं है। भारत और चीन के बीच खुद गहरी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है। रूस की अपनी प्राथमिकताएँ हैं। अन्य सदस्य देशों के भी अलग आर्थिक और भू-राजनीतिक हित हैं।

इसलिए पाकिस्तान का प्रवेश चीन के लिए एक अतिरिक्त रणनीतिक अवसर तो हो सकता है, लेकिन ब्रिक्सके भीतर सहमति बनाना भी कुछ अधिक कठिन हो सकता है।

यही वजह है कि किसी नए सदस्य का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि वह किस बड़े देश के करीब है। यह देखना अधिक महत्वपूर्ण है कि वह संगठन के साझा एजेंडे में कितना योगदान कर सकता है।

2024 के कज़ान शिखर सम्मेलन के बाद इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। इसका उद्देश्य उन देशों को ब्रिक्सकी गतिविधियों से जोड़ना है, जो पूर्ण सदस्य नहीं हैं लेकिन संगठन के साथ आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए यह रास्ता पूर्ण सदस्यता से पहले एक उपयोगी चरण साबित हो सकता है।

ब्रिक्सके लिए भी यह व्यवस्था किसी संभावित नए सदस्य को परखने का माध्यम बन सकती है। किसी देश की आर्थिक क्षमता देखना अपेक्षाकृत आसान है। लेकिन उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता, बहुपक्षीय व्यवहार और संगठनात्मक अनुशासन को परखना अधिक कठिन होता है।

इसलिए पाकिस्तान के लिए यह केवल प्रतीक्षा कक्ष नहीं, बल्कि एक राजनीतिक परीक्षा भी हो सकती है।

ब्रिक्स में पाकिस्तान की संभावित सदस्यता पर बहस करते समय सार्क का अनुभव सामने आना स्वाभाविक है।

1985 में स्थापित सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक सहयोग और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना था। आठ देशों वाला यह संगठन भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद स्वाभाविक क्षेत्रीय मंच था। लेकिन उसकी संभावनाएँ वास्तविक उपलब्धियों में पूरी तरह नहीं बदल सकीं।

भारत-पाकिस्तान तनाव इसका प्रमुख कारण रहा। आतंकवाद और सुरक्षा विवादों ने द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया और अंततः उसका असर पूरे क्षेत्रीय सहयोग पर पड़ा। नवंबर 2014 में काठमांडू में 18वां सार्क समिट हुआ। इसके बाद 19वां शिखर सम्मेलन नहीं हो सका। नवंबर 2016 में इस्लामाबाद में प्रस्तावित सम्मेलन भारत और कुछ अन्य सदस्य देशों के इसमें शामिल न होने के निर्णय के बाद स्थगित हो गया।

यह घटना केवल एक शिखर सम्मेलन के रुकने की कहानी नहीं है। यह बताती है कि जब द्विपक्षीय विवाद किसी बहुपक्षीय संस्था की कार्यप्रणाली पर हावी हो जाते हैं, तो उसकी सामूहिक क्षमता कितनी तेजी से कमजोरपड़ सकती है। ब्रिक्सको सार्क की इस कहानी को गंभीर चेतावनी के रूप में देखना चाहिए। ब्रिक्स का आर्थिक और जनसांख्यिकीय आकार उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से है। लेकिन बड़े बाजार और बड़ी आबादी अपने आप किसी संगठन को प्रभावशाली नहीं बनाते।

सार्क के पास भी विशाल बाजार, युवा आबादी, प्राकृतिक संसाधन और आपसी व्यापार की अपार संभावनाएँ थीं। समस्या क्षमता की नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्वास की थी। राजनीतिक अविश्वास ने आर्थिक सहयोग की संभावनाओं को पीछे धकेल दिया।ब्रिक्सके सामने भी यही जोखिम है।

यदि नए सदस्य अपने द्विपक्षीय विवादों को संगठन के साझा एजेंडे पर हावी करने लगते हैं, तो व्यापार, विकास, तकनीक, वित्त और वैश्विक शासन सुधार जैसे मूल मुद्दों पर ध्यान कमजोर पड़ सकता है।

इसलिए ब्रिक्सका विस्तार तभी सार्थक होगा जब नए सदस्य उसकी सामूहिक क्षमता बढ़ाएँ, न कि उसे नए राजनीतिक संघर्षों में उलझाएँ। पाकिस्तान का ब्रिक्सकी ओर बढ़ना ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका, चीन और रूस के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज है। इसलिए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पाकिस्तान किसी बड़ी शक्ति-प्रतिस्पर्धा में एक रणनीतिक मोहरे की भूमिका निभा सकता है। लेकिन इसे सीधे अमेरिकी रणनीति का हिस्सा घोषित करना अभी जल्दबाजी होगी। अधिक व्यावहारिक विश्लेषण यह है कि पाकिस्तान बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन में अपने विकल्प बढ़ाना चाहता है। पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाए रखते हुए चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी और ब्रिक्सजैसे मंचों से जुड़ाव उसके कूटनीतिक विकल्पों को व्यापक बना सकता है। फिर भी ब्रिक्सके लिए खतरा तब पैदा होगा, जब बाहरी शक्तियाँ संगठन के विस्तार का इस्तेमाल उसके भीतर किसी विशेष देश के खिलाफ नए रणनीतिक समीकरण बनाने के लिए करने लगें।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

जिनपिंग का दिया गया भरोसा भारत के लिए अवसर

डॉ. अरविंद नाथ तिवारी

भारत को इसलिए न तो चीन के प्रति अंधा अविश्वास रखना चाहिए और न ही आंखें बंद करके भरोसा करना चाहिए। सही नीति होगी- 'भरोसा लेकिन सत्यापन के साथ।' चीन जो कहता है, उसे भारत सुने; लेकिन वह क्या करता है, उसका लगातार मूल्यांकन भी करे। सीमा पर शांति, व्यापार में संतुलन, वैश्विक मंचों पर सहयोग और द्विपक्षीय समझौतों का ईमानदारी से पालन- यही वे कसौटियां हैं जिन पर चीन की नई नीति को परखा जाना चाहिए।यदि चीन अपने शब्दों को व्यवहार में बदलता है तो भारत को भी संबंधों को नई ऊंचाई देने में पीछे नहीं रहना चाहिए।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने भारत-चीन संबंधों को लेकर नई उम्मीद पैदा की है। दोनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी कि मतभेदों को विवाद में नहीं बदलने दिया जायेगा। सीमा विवाद का निष्पक्ष और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान तलाशने, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आवाजाही बढ़ाने पर भी सहमति दिखाई दी। आर्थिक और व्यापारिक चिंताओं का समाधान खोजने तथा क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग बढ़ाने की बात भी सामने आई।

इस मुलाकात का एक महत्वपूर्ण पहलू संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा परिषद में बदलाव और व्यापक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर दिया और चीन की ओर से भी सकारात्मक संकेत दिखाई दिया। ब्रिक्स सम्मेलन के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनने के बाद शी जिनपिंग का उनके साथ ग्रुप फोटो में शामिल होना भी कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। तस्वीर में मोदी के एक ओर जिनपिंग और दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का खड़ा होना बदलते वैश्विक समीकरणों का प्रतीक जरूर है।

इन सकारात्मक संकेतों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है- क्या चीन की बदलती भाषा को उसकी बदलती नीति का प्रमाण मान लिया जाए? भारत के लिए यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के साथ संबंधों का इतिहास भरोसे और अविश्वास, दोनों से भरा रहा है। 1962 का भारत-चीन युद्ध आज भी भारतीय जनमानस में गहरे घाव की तरह मौजूद है। उस समय 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' का नारा था लेकिन दोनों देशों के बीच युद्ध ने यह साबित कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मित्रता के नारों से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित और रणनीतिक तैयारी होती है। इसके बाद भी सीमा विवाद समाप्त नहीं हुआ। दशकों तक बातचीत चलती रही, कई समझौते हुए लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। गलवान घाटी की घटना ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास को सामने ला दिया। इसके बाद सीमा पर सैन्य तैनाती और तनाव ने स्पष्ट कर दिया कि चीन के साथ संबंधों में भारत को हमेशा सतर्क रहना होगा। यही कारण है कि इस बार जिनपिंग की ओर से दिए गए भरोसे को भारत को अवसर के रूप में देखना चाहिए, अंतिम समाधान के रूप में नहीं।

कूटनीति में बयान महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है उनका जमीन पर दिखाई देना। यदि चीन वास्तव में भारत के साथ संबंध सामान्य करना चाहता है तो इसका पहला प्रमाण सीमा पर मिलना चाहिए। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम होना, सैनिकों की तैनाती में कमी, पूर्व सहमत व्यवस्थाओं का पालन और सीमा विवाद को बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना ही चीन की नीयत की वास्तविक परीक्षा होगी। व्यापार के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। भारत और चीन दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और व्यापारिक संबंधों में सुधार से दोनों को लाभ हो सकता है लेकिन भारत को यह ध्यान रखना होगा कि व्यापार बढ़ाने के नाम पर चीन पर अत्यधिक आर्थिक या तकनीकी निर्भरता न पैदा हो। भारत को चीन के साथ व्यापार चाहिए लेकिन संतुलित व्यापार चाहिए। सांस्कृतिक संबंधों और लोगों के बीच आवाजाही को बढ़ावा देना भी सकारात्मक कदम है। दोनों देशों के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंध रहे हैं। शिक्षा, पर्यटन, बौद्ध संस्कृति और जनसंपर्क के माध्यम से रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक और सुरक्षा वातावरण भी भरोसेमंद हो।संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर चीन का सकारात्मक रुख भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वैश्विक संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करता रहा है। यदि चीन इस मुद्दे पर वास्तव में भारत के साथ खड़ा होता है तो यह संबंधों में वास्तविक बदलाव का महत्वपूर्ण संकेत होगा। लेकिन यहां भी भारत को शब्दों से अधिक कार्रवाई पर नजर रखनी चाहिए।

मोदी-जिनपिंग-पुतिन की ग्रुप फोटो इसलिए चर्चा में है क्योंकि तस्वीर कभी-कभी कूटनीति का प्रतीक बन जाती है। लेकिन तस्वीर संबंधों की मंजिल नहीं होती। वह केवल यह बताती है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। असली सवाल यह है कि इन खुले दरवाजों से दोनों देश आगे किस दिशा में चलते हैं।

भारत को इसलिए न तो चीन के प्रति अंधा अविश्वास रखना चाहिए और न ही आंखें बंद करके भरोसा करना चाहिए। सही नीति होगी- 'भरोसा लेकिन सत्यापन के साथ।' चीन जो कहता है, उसे भारत सुने; लेकिन वह क्या करता है, उसका लगातार मूल्यांकन भी करे। सीमा पर शांति, व्यापार में संतुलन, वैश्विक मंचों पर सहयोग और द्विपक्षीय समझौतों का ईमानदारी से पालन- यही वे कसौटियां हैं जिन पर चीन की नई नीति को परखा जाना चाहिए।यदि चीन अपने शब्दों को व्यवहार में बदलता है तो भारत को भी संबंधों को नई ऊंचाई देने में पीछे नहीं रहना चाहिए।

कृत्रिम सूर्य के निर्माण में भारतीय उद्यम की दस्तक

मानव सभ्यता का विकास हमेशा ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भर रहा है। आग की खोज से लेकर आज के परमाणु युग तक ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। प्रकृति में ऊर्जा का सबसे विशाल और निरंतर स्रोत सूर्य है जो अरबों वर्षों से बिना रुके प्रकाश और ऊष्मा प्रदान कर रहा है। सूर्य की ऊर्जा का रहस्य नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में छिपा है। वैज्ञानिक दशकों से इसे पृथ्वी पर दोहराने का सपना देख रहे हैं ताकि मानव जाति को ऊर्जा का ऐसा स्रोत मिल सके जो कभी समाप्त न हो। इसी सपने को साकार करने की दिशा में भारत ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। यह छलांग केवल सरकारी प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है बल्कि पहली बार भारत की एक निजी कंपनी ने ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। बेंगलुरु स्थित गहन तकनीकी कंपनी प्रनोस फ्यूजन ने अपने टोकामक संयंत्र प्रज्ञा में प्लाज्मा का निर्माण करके विज्ञान क्षेत्र में नया अध्याय जोड़ा है।

इस महान उपलब्धि का महत्व समझने के लिए वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट पर विचार करना आवश्यक है। आज दुनिया में बिजली उत्पादन का अधिकांश हिस्सा कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। इनके जलने से ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है जिससे जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। विकल्प के रूप में पारंपरिक परमाणु ऊर्जा का उपयोग होता है जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसमें भारी तत्वों को तोड़ा जाता है जिससे ऊर्जा मिलती है लेकिन खतरनाक रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होता है जिसका सुरक्षित निपटान अत्यंत जटिल है। पवन और सौर ऊर्जा स्वच्छ हैं लेकिन मौसम और दिन रात के चक्र पर निर्भर हैं। ऐसे में नाभिकीय संलयन एकमात्र विकल्प है जो पूर्णतः स्वच्छ, सुरक्षित और असीमित है। इसमें कोई खतरनाक कचरा नहीं निकलता और दुर्घटना की संभावना नहीं होती क्योंकि तकनीकी खराबी आने पर संलयन प्रक्रिया स्वतः रुक जाती है।

नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के परमाणुओं मुख्य रूप से हाइड्रोजन के समस्थानिकों को अत्यधिक उच्च तापमान पर आपस में जोड़ा जाता है। जब ये परमाणु मिलते हैं तो भारी तत्व बनता है और अपार ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन पृथ्वी पर इसे अंजाम देना अत्यंत कठिन है। सूर्य के केंद्र में भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण संलयन आसानी से होता है लेकिन पृथ्वी पर ऐसा करने के लिए हमें 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इतने उच्च तापमान पर कोई भी ठोस पदार्थ पिघल कर वाष्प बन जाएगा। पदार्थ की इस गर्म अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है जो पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस अति तप्त प्लाज्मा को किसी सामान्य बर्तन में नहीं रखा जा सकता। यहीं पर टोकामक नामक विशेष तकनीक काम आती है। टोकामक डोनट के आकार की मशीन है जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसी चुंबकीय क्षेत्र की मदद से अत्यधिक गर्म प्लाज्मा को हवा में नियंत्रित रखा जाता है ताकि वह मशीन की दीवारों को स्पर्श न करे।

भारत के लिए यह उपलब्धि विशेष है क्योंकि अब तक नाभिकीय संलयन के क्षेत्र में देश का शोध केवल सरकारी संस्थानों के अधीन था। गुजरात के गांधीनगर स्थित प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान दशकों से इस दिशा में काम कर रहा है। वहां आदित्य और उन्नत टोकामक स्थापित किए गए जिन्होंने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। भारत दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का भागीदार भी है। लेकिन वर्तमान में विज्ञान का स्वरूप बदल रहा है। अब अंतरिक्ष से लेकर परमाणु ऊर्जा तक निजी कंपनियां आगे आ रही हैं। प्रनोस फ्यूजन की सफलता इसी बदलते परिवेश का प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसी निजी भारतीय कंपनी द्वारा स्वयं का टोकामक डिजाइन करना, उसे बनाना और सफलतापूर्वक प्लाज्मा उत्पन्न करना दर्शाता है कि भारत में अब नवाचार और तकनीकी क्षमता की कोई कमी नहीं है।

बेंगलुरु की इस कंपनी ने प्रज्ञा टोकामक को केवल 8 महीने में तैयार किया है। यह विश्व रिकॉर्ड जैसी उपलब्धि है क्योंकि ऐसी मशीनों के निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं। प्रज्ञा कम आयाम अनुपात वाला आधुनिक टोकामक है। इसकी मुख्य विशेषताओं में इसका मुख्य अर्धव्यास 0.40 मीटर और छोटा अर्धव्यास 0.18 मीटर है।

भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी को भारत रत्न देने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई: नड्डा

बेंगलुरु, एजेंसी।

केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारत रत्न देने के बारे में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में कोई चर्चा नहीं हुई है।

उन्होंने यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि पार्टी ऐसे मामलों पर सही समय आने पर फैसला लेती है।

नड्डा ने कहा, ''जहां तक सर्वोच्च नागरिक सम्मान (भारत रत्न) की बात है, पार्टी ऐसे मामलों पर सही समय पर फैसला लेती है। इस मामले पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आपका सुझाव अच्छा है।''

केंद्रीय मंत्री ने यह टिप्पणी उस सवाल के जवाब में की जिसमें पूछा गया था कि क्या देशव्यापी महीने भर चलने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' के समापन पर मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का कोई प्रस्ताव रखा जाएगा।

नड्डा ने विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर तनाशाह की तरह काम करने के लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ''वह दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक नेता हैं''।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार, देश का कायाकल्प और एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में इसकी प्रगति लोकतंत्र और लोगों को साथ लेकर चलने के बिना संभव नहीं होती।

नंदीग्राम उपचुनाव में भाजपा रिकॉर्ड अंतर से जीतेगी : शुभेंदु

हल्दिया (प.बंगाल), एजेंसी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दावा किया कि नंदीग्राम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार एवं उनके पूर्व सहयोगी चंद्रनाथ रथ की मां हसिरानी रथ रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करेंगी।

शुभेंदु ने नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट के अल्पसंख्यक मतदाताओं को संबोधित करते हुए पूछा कि छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में वे राज्य की भाजपा सरकार का समर्थन करेंगे या नहीं।

वह हसिरानी रथ का नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यहां उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) कार्यालय पहुंचे। शुभेंदु ने कहा कि चुनाव कैसे कराया जाता है, वह अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने वहां जुटे लोगों को भरोसा दिलाया कि नंदीग्राम में भाजपा इतने बड़े अंतर से जीतेगी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। शुभेंदु के इस सीट को छोड़ने के कारण यहां चुनाव कराना अनिवार्य हो गया था। शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीट पर जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने भवानीपुर सीट बरकरार रखी और नंदीग्राम सीट छोड़ दी।

उन्होंने कहा, चंद्र (चंद्रनाथ रथ) की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने उस समय के विपक्ष के नेता की मदद की थी।

चंद्रनाथ, शुभेंदु के निजी सहायक के तौर पर काम कर चुके थे। वह छह मई को मध्यमग्राम में कार से जा रहे थे तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन पर कथित तौर पर गोली चलाईं। अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मौत हो गई जबकि चालक घायल हो गया।

इस मामले की शुरुआती जांच राज्य पुलिस और एक विशेष जांच दल ने की थी जिसे बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया। मुख्यमंत्री ने नंदीग्राम के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा, निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से मैंने जो भी वादे किए हैं, उन्हें पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है।

शुभेंदु ने 2021 के चुनाव में नंदीग्राम में बनर्जी को 1,956 मतों के अंतर से हराया था और पांच साल बाद फिर यह सीट जीत ली।

अल्पसंख्यक मतदाताओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, छह अक्टूबर को आपकी परीक्षा होगी कि आप सरकार और मुख्यमंत्री के साथ रहना चाहते हैं या मिलकर काम करना चाहते हैं या नहीं। इस परीक्षा में सफल होना है या असफल, यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं।

पूर्व मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद की रेजीनगर सीट पर अल्पसंख्यक मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या है। आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के प्रमुख हुमायूं कबीर ने दोनों सीट रेजीनगर और नउदा से जीत हासिल करने के बाद रेजीनगर सीट छोड़ दी थी जिसके बाद इस सीट पर चुनाव जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौ मई को सत्ता संभालने के बाद राज्य की भाजपा सरकार विकास से जुड़ी कई पहल कर रही है और वह अगले 56 माह तक पश्चिम बंगाल के लोगों के कल्याण व राज्य की प्रगति के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा, हम अपने वादों और 'संकल्प पत्र' (चुनाव घोषणापत्र) में किए गए वादों को पूरा करने का काम आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि अगले 56 महीनों में बंगाली विरासत को बहाल करना।''

अधिकारी ने फिर कहा कि नंदीग्राम में पिछली टीएमसी सरकार के दौरान जिन भाजपा कार्यकर्ताओं को अत्याचार झेलने पड़े थे, उन्हें काम, रहने की जगह और खाना दिया जाएगा। उन्होंने कहा, नंदीग्राम के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज झूठे आपराधिक मामलों को वापस लेना मेरी जिम्मेदारी है।

महाराष्ट्र सीईटी परीक्षा से जुड़ी शिकायतों की जांच एसआईटी करेगी : फडणवीस

मुंबई, एजेंसी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि इंजीनियरिंग समेत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए राज्य की प्रवेश परीक्षा, महाराष्ट्र-सीईटी से जुड़ी शिकायतों की व्यापक जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो कार्रवाई की जाएगी।

हाल ही में, राज्य भर के शिक्षकों और छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने साझा प्रवेश परीक्षा (सीईटी) से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी।

फडणवीस ने निर्देश दिया है कि इन सभी शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज की जाए और पुलिस के संयुक्त आयुक्त इनकी जांच करें। उन्होंने कथित डेटा लीक की फॉरेंसिक ऑडिट का भी आदेश दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की कुछ परीक्षाओं को टालने का फैसला पहले ही कर लिया है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि एमपीएससी परीक्षाओं के सिलसिले में बनाई गई समिति के अध्यक्ष की बातों का गलत मतलब निकाला गया। फडणवीस ने कहा, फिलहाल कोई भी परीक्षा ऑनलाइन आयोजित नहीं की जा रही है, और साथ ही कहा कि भविष्य में कोई भी फैसला छात्रों से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा।

फडणवीस ने कहा कि सरकार राज्य में बारिश की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है, क्योंकि कई जिलों में 30 दिनों से बारिश नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में जिलेवार प्रस्तुतियों के साथ इस मुद्दे पर लगभग 45 मिनट तक चर्चा हुई और सरकार ने संभावित कमी और सूखे जैसे हालात से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के नियमों के तहत, सूखे या पानी की कमी की स्थिति में मदद के लिए पात्रता का पता लगाने के वास्ते आधिकारिक सर्वे पांच अक्टूबर के बाद किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, लेकिन हम पांच अक्टूबर तक इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमने शुरुआती जानकारी इकट्ठा करना और दूसरे उपायों की तैयारी शुरू कर दी है।

उन्होंने भरोसा दिलाया, हम किसानों को हालात के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। राज्य सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी।

उत्तराखंड: केदारनाथ पैदल मार्ग खुला

रुद्रप्रयाग/देहरादून, एजेंसी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन के कारण तीन दिन से रुकी केदारनाथ यात्रा मंगलवार को बहाल हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानसून के दौरान बंद की गई केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी मंगलवार से शुरू कर दी गई। गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीड़वासा हेलीपैड के पास रविवार को बोल्डर और पत्थर गिरने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा रोक दी गई थी।

यात्रा बहाल होने से पहले केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे 7,350 श्रद्धालुओं को बचाव दलों की निगरानी में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाला गया।

उज्जैन में दीपोत्सव में शामिल होंगे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन

भोपाल, एजेंसी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन में उनके 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उज्जैन में 17 सितंबर को आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे।

इस आयोजन के मद्देनजर भाजपा ने शिप्रा नदी के घाटों और महाकाल लोक क्षेत्र में करीब 25 लाख दीप जलाए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में जल, थल और नभ में भारत का परचम लहरा रहा है, तो वहीं समाज के हर वर्ग के उत्थान में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा, नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को सारा देश सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाता है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में विकास का दीप जलाने एवं अभियान का आरम्भ करने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 17 सितंबर को मध्यप्रदेश पधार रहे हैं। यादव ने कहा, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष का मध्यप्रदेश में आत्मीय स्वागत करता हूं।

सार समाचार

लोकतंत्र के हित में भाजपा को सत्ता से हटाना जरूरी: अखिलेश

लखनऊ, एजेंसी। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि राज्य के भविष्य और आने वाली पीढ़ी की खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से हटाना लोकतंत्र के हित में है। सपा मुख्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, यादव ने पार्टी के डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चौपट है और भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है।

उन्होंने कहा कि इसलिए भाजपा सरकार को सत्ता से हटाना ही एकमात्र उपाय है। यादव ने कहा कि सपा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) वर्ग को एकजुट कर उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार को हटाने के लिए संकल्पित है।

छत्तीसगढ़ तेजी से खेल स्थल के तौर पर उभर रहा है: साय

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को कहा कि राज्य तेजी से देश के उभरते खेल स्थल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री साय ने आज नवा रायपुर स्थित फेयरवे गोल्फ एंड कंट्री क्लब रिजॉर्ट में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'डीपी वर्ल्ड नवा रायपुर ओपन 2026' कार्यक्रम को संबोधित किया।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री साय और डीपी वर्ल्ड पीजीआईटी के अध्यक्ष कपिल देव ने नवा रायपुर ओपन 2026 का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टूर्नामेंट आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की नई पहचान बनेगा और नवा रायपुर को देश-दुनिया के प्रमुख गोल्फ स्थल के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

साय ने प्रतियोगिता की आकर्षक ट्रॉफी का अनावरण किया तथा देश-विदेश से आए पेशेवर गोल्फ खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ की धरती पर स्वागत किया।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने गोल्फ कोर्स पर स्वयं गोल्फ में हाथ आजमाया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

प्रावधान ठीक हुए तो यूसीसी का विरोध नहीं करेंगे: विजय कुमार चौधरी

पटना, एजेंसी।

बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि पार्टी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का अध्ययन करेगी और अगर विधेयक के प्रावधानों में कोई आपत्तिजनक बात नहीं होगी तो पार्टी बिना वजह इसका विरोध नहीं करेगी।

प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष चौधरी ने पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही।

शाह ने कहा था कि 2029 तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित 22 राज्यों में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चौधरी ने इस मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कड़े रुख से जदयू को अलग बताते हुए कहा कि राजद ने यूसीसी को मुसलमानों के हितों के खिलाफ बताते हुए बिहार में इसे लागू करने का विरोध करने का संकल्प लिया है।

माकपा ने केरलम में संगठनात्मक बदलाव की घोषणा की

कोझिकोड (केरलम), एजेंसी। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने मंगलवार को केरलम में बड़े संगठनात्मक बदलावों की घोषणा की। पार्टी ने प्रमुख नेताओं पी जयराजन, एम बी राजेश और वी शिवनकुट्टी को राज्य सचिवालय में शामिल किया तथा युवा नेताओं और महिलाओं को संगठन में अधिक जिम्मेदारी देने का फैसला किया। तीन दिवसीय विस्तारित राज्य समिति की बैठक के बाद माकपा के राज्य सचिव एम वी गोविंदन ने कहा कि पार्टी ने चुनावी हार की सामूहिक जिम्मेदारी स्वीकार की है और अब संगठनात्मक कमियों को दूर करना हैं।

राम मंदिर निर्माण में शामिल कंपनियों को बैंक गारंटी देनी होगी: नृपेंद्र मिश्रा

अयोध्या, एजेंसी।

श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण में शामिल कंपनियों को 'बैंक गारंटी' देनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आने वाले वर्षों में उनके काम की गुणवत्ता बनी रहे। मिश्रा ने अयोध्या की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन संवाददाताओं से कहा कि यह मुद्दा मंदिर निर्माण में शामिल कंपनियों, विशेष रूप से लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) और टाटा को अंतिम भुगतान पर चर्चा के दौरान उठा।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में जैसे जैसे काम आगे बढ़ा कंपनियों को लगातार भुगतान किए जाते रहे हैं। अब प्रक्रिया अंतिम भुगतान और जरूरी समायोजन के चरण में पहुंच गई है।

मिश्रा ने प्रक्रिया को समझाते हुए कहा, पिछले पांच वर्षों के दौरान काम की प्रगति के आधार पर भुगतान किया जाता था लेकिन अब समायोजन करना होगा।

उन्होंने कहा कि अंतिम भुगतान प्रक्रिया के तहत हर कंपनी को मंदिर के निर्माण कार्य के संबंध बैंक गारंटी देनी होगी ताकि यह सुनिश्चत हो सके कि आने वाले वर्षों में उनके काम की गुणवत्ता बनी रहेगी।

मिश्रा ने कहा कि बैठकों के दौरान बैंक गारंटी से संबंधित कटौती के मुद्दे पर भी चर्चा की गई।

उन्होंने बताया कि अंतिम बिल का प्रस्तावित तृतीय-पक्ष ऑडिट भी एक अन्य प्रमुख मुद्दा था।

मिश्रा ने कहा कि टाटा पहले से ही परियोजना प्रबंधन परामर्श में शामिल था लेकिन ट्रस्ट ने अतिरिक्त ऑडिट के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को शामिल करने का भी फैसला किया था।

उन्होंने कहा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को अंतिम बिल का कम से कम 60 से 70 प्रतिशत ऑडिट करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, इसका चयन कंपनियों के संबंधित ऑर्डर और लागू प्रतिशत गुणांकों के आधार पर किया जाएगा।

मिश्रा ने कहा कि मंदिर का निर्माण पूरा होने के साथ अब ध्यान अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और अन्य संबंधित कार्यों पर है।

उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के अंदर एक सभागार और परिसर के बाहर एक अन्य सुविधा निर्माणाधीन है जिसके काम में लगभग तीन से चार महीने की देरी हुई।

एलसी-1 में चुनावी घमासान, मुद्दों पर टिकी छात्रों की नजर

नई दिल्ली, साहस समाचार।

- सचिव पद पर यशवंत मिश्रा और अरशद आमने-सामने; पानी, प्लेसमेंट, कैंटीन और पुस्तकालय बने चुनावी बहस के केंद्र।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव की सरगर्मी के साथ प्रतिष्ठित लॉ सेंटर-1 (एलसी-1) भी चुनावी रंग में रंग गया है। उत्तर परिसर स्थित उमंग भवन और आसपास के अध्ययन क्षेत्रों में प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। सुबह से शाम तक विद्यार्थियों के बीच संपर्क, पोस्टर और चुनावी नारे माहौल को गर्म कर रहे हैं। अध्यक्ष पद पर उमंग पाठक और तुषार कुशवाहा के बीच मुकाबला चर्चा में है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर शिवम गौतम और निशांत राणा अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें सचिव पद पर हैं, जहां यशवंत मिश्रा और अरशद के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है।

एलसी-1 का इस बार का चुनाव केवल छात्र संगठनों की ताकत आजमाने तक सीमित नजर नहीं आ रहा। पेयजल की गुणवत्ता, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप, कैंटीन की व्यवस्था, पुस्तकालय के समय और वाई-फाई जैसी बुनियादी सुविधाएं चुनावी बहस के केंद्र में आ गई हैं। विद्यार्थियों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि चुनाव के बाद इन मुद्दों को प्रशासन के सामने कितनी मजबूती से उठा पाएगा।

सचिव पद के प्रत्याशी यशवंत मिश्रा ने अपने अभियान को मुद्दा आधारित रखने का दावा किया है। उनका कहना है कि विधि के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण और करियर के अवसर बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसी वजह से उनके एजेंडे में प्लेसमेंट एवं इंटर्नशिप सेल का पुनर्गठन प्रमुख मुद्दा है।

यशवंत के मुताबिक, यदि वे निर्वाचित होते हैं तो एक पारदर्शी करियर एवं प्लेसमेंट व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम करेंगे, ताकि विद्यार्थियों को अधिवक्ताओं, लॉ फर्मों, कॉरपोरेट संस्थानों और अन्य कानूनी संगठनों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत प्रयास हो सकें। पानी का मुद्दा भी चुनावी चर्चा में तेजी से उभरा है।

उमर खालिद एक राष्ट्रवादी हैं : हरिप्रसाद

बेंगलुरु, एजेंसी। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद ने जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को मंगलवार को एक राष्ट्रवादी बताया। हरिप्रसाद ने कहा कि खालिद पर बनी वृत्तचित्र फिल्म की एनएलएसआईयू में स्क्रीनिंग का विरोध करने वाले एबीवीपी को जेल में बंद नेता के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सितंबर 2020 में गिरफ्तार किए गए खालिद पर फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मुख्य साजिशकर्ताओं'' में से एक होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

नंदीग्राम उपचुनाव पर तृणमूल ने गठबंधन की पेशकश की: कांग्रेस

कोलकाता, एजेंसी।

कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस ने उसके केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क कर कहा था कि छह अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में वह अपनी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार है। हालांकि, तृणमूल ने इस दावे को खारिज कर दिया।

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में गठबंधन को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है। यह दावा तृणमूल के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है जो वर्षों से कहती रही है कि वह पश्चिम बंगाल में अकेले ही भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम है और राज्य में व्यापक चुनावी तालमेल के लिए कांग्रेस की ओर से किए गए प्रयासों को बार-बार खारिज करती रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य ने दावा किया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल खेमे ने करीब 15 दिन पहले नयी दिल्ली में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से संपर्क किया था। उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि नंदीग्राम उपचुनाव कांग्रेस लड़े, जबकि रेजीनगर सीट पर तृणमूल चुनाव लड़े।

नीति का उल्लंघन कर रहे हैं रियायती दरों पर जमीन पाने वाले निजी अस्पताल: सुरजेवाला

चंडीगढ़, एजेंसी।

कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को आरोप लगाया कि हरियाणा में निजी अस्पतालों को रियायती दरों पर जमीन आवंटित की गई, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं बनाया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की नीति के तहत गरीब मरीजों को मुफ्त या रियायती दर पर इलाज मिले।

सुरजेवाला ने एक बयान में हरियाणा सरकार से मांग की कि रियायती दरों पर जमीन पाने वाले प्रत्येक अस्पताल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) मरीजों को दिए गए इलाज का सार्वजनिक रिकॉर्ड जारी किया जाए।

उन्होंने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को रियायत देने के लिए 2022 में एक नीति जारी की थी।

उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था लागू करने की मांग 2016 से उठाई जाती रही है, लेकिन भाजपा सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में भी गरीब मरीजों को कथित तौर पर उनका उचित लाभ नहीं मिला।

उन्होंने कहा, ''2022 से चार साल बीत चुके हैं, फिर भी नीति का क्रियान्वयन लगभग शून्य है।'' उन्होंने सवाल किया कि अनिवार्य शर्तों को पूरा करने में कथित तौर पर विफल रहने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

दुष्कर्म पीड़िता को गर्भ रखने के लिए मजबूर करना सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन : अदालत

जबरन मां बनाना सम्मान के अधिकार का उल्लंघन: हाईकोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि दुष्कर्म पीड़िता को अपराध की वजह से गर्भ ठहरने की स्थिति में उसकी मर्जी के बिना मां बनने की जिम्मेदारी थोपना, सम्मान के साथ जीने के उसके अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा।

अदालत ने यह टिप्पणी 15 साल की दुष्कर्म पीड़िता की उस याचिका को स्वीकार करते हुए की, जिसमें उसने 30 हफ्ते के गर्भ को नष्ट करने की अनुमति मांगी थी।

चिकित्सा गर्भपात अधिनियम (एमटीपी) की धारा तीन के तहत, कुछ विशेष श्रेणियों की महिलाओं की कानूनी जरूरतों को पूरा करने पर 20 से 24 हफ्ते तक के गर्भ को नष्ट करने की अनुमति देता है। न्यायमूर्ति मधु जैन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद मामला बताते हुए कहा कि गर्भावस्था के कानूनी समय-सीमा के पार कर जाने करे अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता।

अदालत ने आठ सितंबर को दिये आदेश में कहा, यौन उत्पीड़न के मामलों में, पीड़िता को उत्पीड़न से ठहरे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर करना और इस तरह उसकी मर्जी के बिना उस पर मातृत्व की जिम्मेदारी डालना, उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा। फैसले में कहा गया कि अपने शरीर के संबंध में महिला के अधिकार में यह तय करने का अधिकार भी शामिल है कि वह मां बनना चाहती है या नहीं।

अदालत ने कहा कि यौन हमले की शिकार महिला को उस अपराध के परिणामस्वरूप गर्भ ठहरने की वजह से बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करने से उसे दीर्घकालिक शारीरिक और मानसिक आघात का सामना करना पड़ सकता है।

न्यायाधीश ने कहा कि भले ही गर्भावस्था का समय अधिक होने के कारण अधिक चिकित्सा सतर्कता की जरूरत है, लेकिन केवल इस वजह से नाबालिग को अपने शरीर पर अधिकार, सम्मान और बच्चे को जन्म देने से जुड़े फैसले लेने के अधिकारों पर विचार करने से वंचित नहीं किया जा सकता।

अदालत ने साथ ही कहा कि किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया के लिए महिला की शारीरिक स्थिति और चिकित्सा व्यवहार्यता की जांच, तथा सभी जरूरी सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 या 32 के तहत प्रदत्त अधिकार का इस्तेमाल करते हुए और एमटीपी अधिनियम के कानूनी ढांचे को ध्यान में रखते हुए अदालत को नाबालिग पीड़िता के हितों और कल्याण को उचित प्राथमिकता देनी चाहिए।

अदालत ने कहा कि उसे यह कहना पड़ रहा है कि ऐसे मामले 'गहरी पीड़ा' छोड़ जाते हैं।

उसने इस तथ्य पर संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता केवल 15 साल की बच्ची है, जो पहले ही एक भयानक यौन हमले का सदमा झेल चुकी है और उसकी मुश्किल स्थिति को और बढ़ाने वाली बात यह है कि उसने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है। अदालत ने कहा कि जिस उम्र में किसी बच्चे को सुरक्षा और देखभाल मिलनी चाहिए और उसे सुरक्षित व सम्मानजनक माहौल में बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उस उम्र में उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनका सामना किसी भी बच्चे को कभी नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति ने कहा, इस अदालत की नजर में, 15 साल की बच्ची को केवल इसलिए 'मां' नहीं कहा जा सकता क्योंकि यौन हिंसा के कारण उसे गर्भवती होने के लिए मजबूर किया गया है।

इसमें कहा गया कि अदालत के संज्ञान में यह तथ्य है कि माता-पिता दोनों के न रहने से लड़की के हालात और मुश्किल हो गए हैं। अदालत ने कहा कि कानून भले ही उपाय और प्रक्रियाएं उपलब्ध कराए, लेकिन उसका कोई भी आदेश उस सदमे को मिटा नहीं सकता जो बच्ची ने सहा है।

सार समाचार

पितृपक्ष मेले में चार साल में करीब चार गुना बढ़े पर्यटक

पटना,एजेंसी। बिहार के गयाजी में पितरों के मोक्ष की कामना लेकर उमड़ने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले चार वर्षों में पितृपक्ष मेले में आने वाले पर्यटकों की संख्या करीब चार गुना बढ़ी है। वर्ष 2022 में 9.40 लाख पर्यटकों की संख्या दर्ज की गई थी जो 2025 में बढ़कर 34.79 लाख तक पहुंच गई। पर्यटन विभाग ने इस वर्ष करीब 50 लाख लोगों के संभावित आगमन को ध्यान में रखते हुए गयाजी से पुनपुन तक व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। 25 सितंबर से शुरू होने वाले पितृपक्ष मेले में पर्यटकों को आवास, परिवहन, पिंडदान, भोजन और पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराने की योजना है। पितृपक्ष मेले में लोगों की बढ़ती संख्या पिछले चार वर्षों के आंकड़ों से साफ दिखाई देती है।

छत्तीसगढ़ी लोकधुनों पर झूमा रायगढ़

रायगढ़, एजेंसी। कला, संस्कृति और संगीत की समृद्ध परंपरा के लिए देश-दुनिया में पहचान रखने वाले रायगढ़ के 41वें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह का सोमवार की देर शाम भव्य एवं गरिमामय शुभारंभ हुआ। राज्यपाल रमेन डेका ने भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। कला, संस्कृति, संगीत और नृत्य की गौरवशाली परंपरा को समर्पित 41वें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह का पहला दिन कला और भक्ति के विविध रंगों से सजा। समारोह के शुभारंभ के बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू हुआ और देर रात पद्मश्री अनुज शर्मा की छत्तीसगढ़ी लोकसंगीत से सजी प्रस्तुति ने समां बांध दिया। उनकी लोकप्रिय लोकधुनों पर दर्शक मंत्रमुग्ध होकर झूमते रहे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा रामलीला मैदान गूंज उठा। पद्मश्री अनुज शर्मा ने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत अहो भजो मन गणपति गणराज, सुमति मन जैसी भक्तिमय प्रस्तुति से की।

पीएम आवास योजना पर बघेल-शर्मा आमने-सामने, आंकड़ों को लेकर 80 मिनट चली बहस

रायपुर,एजेंसी।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लंबे समय से जारी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच सोमवार को उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर प्रेस क्लब में आमने-सामने हुए। करीब एक घंटे 20 मिनट चली खुली बहस में दोनों नेताओं ने योजना की स्वीकृति, निर्माण, केंद्रीय सहायता और राज्य सरकार के खर्च को लेकर अपने-अपने आंकड़े पेश किए तथा एक-दूसरे के दावों पर सवाल उठाए।

प्रदेश की राजनीति में यह पहला मौका रहा, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो बड़े नेताओं ने किसी मुद्दे पर एक मंच से सीधे बहस की। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर दोनों नेताओं के बीच पिछले दिनों चुनौती और प्रतिचुनौती के बाद यह खुली बहस तय हुई थी। मंत्री शर्मा ने बहस के दौरान दावा किया कि केंद्र ने 17 लाख 75 हजार आवास पूर्ण किए हैं और भारत सरकार की वेबसाइट पर इसके पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, 2025-26 में छत्तीसगढ़ ने देश में सर्वाधिक पीएम आवास बनाए।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में वित्तीय वर्ष में स्वीकृत आवास पूरे नहीं हुए। पांच वर्ष में वित्तीय स्वीकृति 3,900 करोड़ रुपये की थी और कांग्रेस सरकार ने तीन लाख आवास पूर्ण किए, जबकि भाजपा सरकार ने ढाई वर्ष में 16 हजार करोड़ रुपये खर्च किए। इसके जवाब में बघेल ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के आंकड़े रखते हुए कहा, 2018 में 3 लाख 48 हजार 960 घर स्वीकृत हुए। 1 लाख 39 हजार मकान पूर्ण हुए। 2020-21 में 1 लाख 97 हजार 811 का लक्ष्य था।

1 लाख 22 हजार आवास पूरे हुए। कोरोना काल में किसी सरकार के पास पैसा नहीं था। बघेल ने कहा कि 2022-23 में पोर्टल बंद कर दिया गया था। राज्य सरकार ने भारत सरकार से अपना पैसा मांगा और इसके लिए पत्राचार भी किया गया। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 18 लाख आवास शेष थे और कांग्रेस सरकार ने 6 लाख 97 हजार आवास स्वीकृत किए। आंकड़े पेश किए जाने के दौरान शर्मा ने कहा, एक बार गणना पूरी करिए। गणित सही होनी चाहिए।

मंत्री शर्मा ने बघेल के पोर्टल बंद होने के दावे को खारिज करते हुए कहा,पीएम आवास का पोर्टल बंद नहीं था। कोरोना काल में भी पैसा आ रहा था। उन्होंने कहा कि विषय पोर्टल का नहीं था, बल्कि भूपेश बघेल ने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास है तो प्रधानमंत्री ही जाने। पूरी राशि हम अपनी तरफ से देंगे। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र ने राज्य को राशि जारी नहीं की थी और पोर्टल बंद था। उन्होंने कहा, सही क्या था, पत्रकार खुद ही खोज लेंगे कि कौन सच बोल रहा है। उन्होंने दावा किया कि 25 सितंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक 18 लाख मकान स्वीकृत किए गए।

बहस के दौरान मंत्री शर्मा ने तत्कालीन मंत्री टीएस सिंहदेव का उल्लेख करते हुए कहा, आपके मंत्री टीएस सिंहदेव ने लिखा कि राशि नहीं मिल पाने की वजह से पीएम आवास नहीं बन पाए, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। बघेल ने जवाब दिया कि कोरोना काल में केंद्र ने राशि ही जारी नहीं की। इस पर मंत्री शर्मा ने कहा, आपने कहा था कि प्रधानमंत्री का नाम है तो प्रधानमंत्री ही जाने। उन्होंने आगे कहा, पोर्टल बंद था, ये कहना गलत था। ग्रोक से पूछिए, सच बताएगा। बघेल ने कहा कि कोरोना काल में किसी राज्य के पास पैसा नहीं था और आवास बनाने के लिए उनकी सरकार ने आरबीआई से ऋण लिया था।

कैबिनेट ने 2031 तक 42,490 करोड़ के कार्य जारी रखने को दी मंजूरी

भोपाल, एजेंसी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 42,490 करोड़ रुपये के कार्यों को वर्ष 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसमें 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। बैठक में स्कूलों के उन्नयन के साथ उनके लिए पद स्वीकृत करने सहित अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि जनजातीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 1973-74 से 1997-98 तक नियुक्त उप शिक्षक, उपशाला शिक्षक, प्रशिक्षण शिक्षक, कनिष्ठ बोर्ड से चयनित शिक्षक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत नियुक्त शिक्षक और सहायक शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान देने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ एरियर राशि के भुगतान को भी स्वीकृति दी गई।

जनजातीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 2016-17 में माध्यमिक शालाओं के उन्नयन के तहत चार हाई स्कूलों के पदों की स्थिति तय करने को भी मंजूरी दी गई। वही जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना को लगातार जारी रखने और गोंड वृहद सिंचाई परियोजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। ये परियोजनाएं 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं में शामिल हैं। जबकि मंत्रिपरिषद ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों को लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर उपलब्ध कराने से संबंधित नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को दी गई 250 रुपये की अतिरिक्त सहायता से संबंधित कार्रवाई का अनुमोदन किया गया।

दूसरी ओर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत खाद्यान्न उपार्जन के लिए निर्धारित ऋण सीमा के पुनर्भुगतान के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त अशासकीय विधि महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल को यूजीसी का सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

बिना गेट पास सरसों ले जा रही दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त

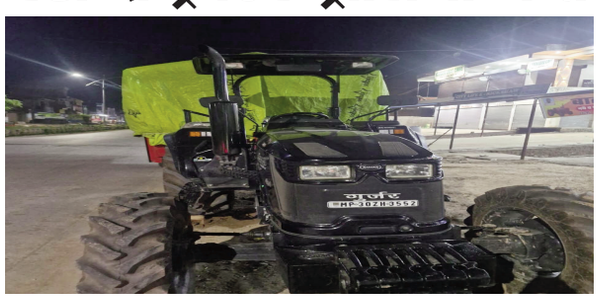

भिण्ड, साहस समाचार।

एसडीएम गोहद के नेतृत्व में क्षेत्र के भ्रमण के दौरान कृषि उपज के परिवहन की जांच में बिना वैध गेट पास सरसों ले जा रही दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया गया। दोनों वाहनों में कुल 316.15 क्विंटल सरसों पाई गई।

जांच के दौरान पहली ट्रैक्टर-ट्रॉली में 123.95 क्विंटल तथा दूसरी में 192.20 क्विंटल सरसों लदी मिली। दोनों वाहनों के चालक कृषि उपज के परिवहन के लिए आवश्यक वैध गेट पास प्रस्तुत नहीं कर सके।

प्रकरण की जांच में बिना वैध गेट पास कृषि उपज का परिवहन मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 19(6) के प्रावधानों के विपरीत पाया गया। इसके बाद दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को नियमानुसार जब्त कर लिया गया। मंडी शुल्क से संबंधित प्रकरणों में धारा 19(4) के तहत चालानी कार्रवाई भी की गई। प्रशासन के अनुसार दोनों मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा रही है। प्रशासन ने कृषि उपज का परिवहन करने वाले किसानों, व्यापारियों और वाहन चालकों से निर्धारित गेट पास एवं आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की अपील की है।

सनकी प्रेमी ने महिला को जिंदा जलाया, उपचार के दौरान मौत

रायपुर, एजेंसी। राजधानी रायपुर के माना एयरपोर्ट क्षेत्र में एक सनकी प्रेमी ने एक महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया।

गंभीर रूप से झुलसी महिला बीती रात मेकाहारा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने आज मंगलवार को पोस्टमार्टम उपरांत शव परिजनों को सौप दिया है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब साढ़े 9 से 10 बजे के बीच माना बस्ती से बरौंदा जाने वाली सड़क पर एटीसी बिल्डिंग के पीछे ग्रामीणों और राहगीरों ने एक महिला को झुलसी हालत में चीखते-चिल्लाते देखा। सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और महिला को उपचार के लिए मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला करीब 65 से 70 फीसदी झुलसी हुई थी। सोमवार देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरिबाला सिंह को हाई कोर्ट भी राहत नहीं

भोपाल, एजेंसी।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को उच्च न्यालायय से भी कोई राहत नहीं मिली। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध किया।

दरअसल, ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में जेल में बंद गिरिबाला सिंह की करीब तीन सप्ताह से लंबित जमानत याचिका पर आज उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय ने गिरिबाला सिंह और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनीं। सीबीआई की ओर से जवाब के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया, साथ ही जमानत का विरोध करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की है।

सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह द्वारा दलील दी गई कि उनकी उम्र और बीमारी को देखते हुए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि गिरिबाला सिंह जांच और कार्रवाई में पूरी तरह सहयोग करेंगी। वहीं, सीबीआई की ओर से मामले में जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया। न्यायालय ने सीबीआई को समय देते हुए अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित कर दी। फिलहाल गिरिबाला सिंह जेल में हैं और उनकी जमानत पर अंतिम फैसला अगली सुनवाई में होने की संभावना है। गिरिबाला सिंह के वकील सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जस्टिस अजय कुमार निरंकारी को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष की ओर से वकील कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। उनकी ओर से कहा गया कि गिरिबाला सिंह की उम्र को देखा जाए। उन्होंने बताया कि गिरिबाला सिंह की ओर से कोई भी गलती नहीं की गई है। उनकी ओर से नहीं उकसाया गया, जिससे ट्विशा ने आत्महत्या की। न ही इस केस में उनकी तरफ से ऐसा कोई कृत्य किया गया है, जिससे कि यह कहा जा सके कि वो किसी भी जुर्म में संलिप्त हैं।

भाजपा के नेता विलेन के रूप में काम करते हैं: डॉ. इरफान अंसारी

रांची, एजेंसी।

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आज भाजपा की नीतियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि राज्यवासियों को एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। डॉ अंसारी ने जामताड़ा के चादर डिपो में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एमएमडीआर एक्ट में किया गया संशोधन झारखंड के हितों के खिलाफ है और यह काला कानून है।

इसके पीछे की मंशा झारखंड को उसके अधिकारों और संसाधनों से वंचित करना है। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से राज्य को मिलने वाले हजारों करोड़ रुपये के राजस्व पर गंभीर असर पड़ेगा, जिसका सीधा नुकसान झारखंड की जनता और विकास योजनाओं को होगा। डॉ अंसारी ने कहा, यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति, पार्टी या समुदाय की नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड की लड़ाई है। हमें जात-पात और हिंदू-मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर अपने जल, जंगल, जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा।

उन्होंने ने कहा कि भाजपा की राजनीति जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति बनकर रह गई है। भाजपा के नेता विलेन की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि जननायक राहुल गांधी जी देश और जनता के असली मुद्दों की लड़ाई लड़ने वाले हीरो हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को चुनौती देते हुए डॉ. अंसारी ने कहा, अगर आप वास्तव में झारखंड की जनता की चिंता करते हैं तो विकास की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, युवाओं के भविष्य की बात कीजिए।

झारखंड के अधिकार और एमएमडीआर से जुड़े मुद्दे पर मजबूती से जनता के साथ खड़े होते तो मुझे खुशी होती। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समाज को लेकर भ्रम और भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को असली मुद्दों से भटकाकर जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करना झारखंड के हित में नहीं है।

भस्म आरती में राजा स्वरूप में सजे महाकाल

उज्जैन, एजेंसी। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार तड़के भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर भगवान महाकाल की भस्म आरती विशेष श्रृंगार के साथ संपन्न हुई। सुबह करीब चार बजे मंदिर के कपाट खुलने के बाद गर्भगृह में स्थापित देवी-देवताओं का पूजन किया गया। इसके बाद भगवान महाकाल का हरिओम जल से अभिषेक कर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और फलों के रस से तैयार पंचामृत से पूजन-अभिषेक किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल का भांग, चंदन और विभिन्न आभूषणों से दिव्य श्रृंगार किया गया। भगवान को रजत चंद्र, त्रिशूल और त्रिपुंड धारण कराया गया। ड्रायफ्रूट से किए गए विशेष श्रृंगार में बाबा महाकाल को राजा स्वरूप प्रदान किया गया। शेषनाग का रजत मुकुट, रजत मुण्डमाल, रुद्राक्ष की माला और सुगंधित पुष्पों की मालाओं से भगवान का अलंकरण किया गया।

अभियंता विकास कार्यों को आकार देते हैं, नई संभावनाएं खोलते हैं: डॉ. यादव

भोपाल,एजेंसी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नया मार्ग विकास का रोडमैप तैयार करता है और भविष्य की आर्थिक गतिविधियों की संभावनाएं भी खोलता है। उन्होंने प्रदेश में सीमेंट का उपयोग किए बिना सड़कें बनाने की पहल को सराहनीय बताते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने स्तर पर बजट जुटाकर सड़कें बनाने के निर्णय को भी अच्छा बताया। डॉ. यादव मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में अभियंता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि अभियंता मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग को नई दिशा दी। अभियंता में इंजन जैसी क्षमता होती है, जो विकास कार्यों को आकार देती है। उन्होंने कैलाश पर्वत की चट्टानों को काटकर किए गए निर्माण का उदाहरण देते हुए उस दौर की कला और कौशल का उल्लेख किया। उन्होंने नए और पुराने संसद भवन में मुरैना और विदिशा के पत्थरों तथा कला के उपयोग का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की सराहना करते हुए कहा कि विभाग ने अभियंताओं को पांच तरह के पुरस्कार देकर उनके कार्यों को सम्मानित किया है। कार्यक्रम में 95 और 86 वर्ष की उम्र के सेवानिवृत्त अभियंताओं का भी सम्मान किया गया।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि अभियंताओं का काम चुनौती देखकर रुकना नहीं, बल्कि समाधान तलाशना है। अभियंता की कार्यप्रणाली के लिए खोजी स्वभाव, अनुशासन और परफेक्शन जरूरी है। सकारात्मक विचारों को दबाने के बजाय उन पर मंथन कर उन्हें आकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अभियंताओं की ट्रेनिंग का काम नौ महीने में 85 प्रतिशत पूरा हो चुका है। बिना प्रशिक्षण के अभियंता नई चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। सिंह ने बताया कि विभाग सीएसआईआर-एएमपीपीआरआई के साथ सीमेंट विहीन कांक्रीट के उपयोग के लिए समझौता करेगा। इसके तहत कुछ सड़कें संस्थान को दी जाएंगी, जहां बिना तराई के भी बेहतर सड़क निर्माण की तकनीक का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के इस नवाचार को ओडिशा ने भी अपनाया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों शिलान्यास किया।

उन्होंने कहा कि अभी एमपीआरडीसी करीब 30 हजार करोड़ रुपये के काम करा रहा है। आने वाले समय में यह राशि बढ़ाकर दो लाख करोड़ रुपये के काम कराने का लक्ष्य है।

उन्होंने अभियंताओं के लिए निर्माण को जिम्मेदारी, लोक कल्याण को लक्ष्य, गुणवत्ता को पहचान, नवाचार को शक्ति और तकनीक को भविष्य बताया। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने कहा कि एमपीआरडीसी ने कई स्थानों पर फ्लाईओवर और बायपास बनाकर ब्लैक स्पॉट खत्म किए हैं। वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए बेहतर प्लानिंग, एक्जीक्यूशन और नवाचार पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने मीरा के पसरे से खरीदा आशीर्वाद का दीया

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सड़क किनारे पसरा लगाकर मिट्टी के दीये बेच रही मीरा के लिए आज का दिन अचानक बेहद खास बन गया।

रोज की तरह वह अपने छोटे से पसरे पर दीये सजाकर ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का काफिला अचानक उसके पसरे के पास जाकर रुक गया।

मुख्यमंत्री साय ने मीरा के पसरे पर रखे मिट्टी के दीयों को देखा और 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत आयोजित होने वाले 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम के लिए वहीं से एक दीया खरीदा। मुख्यमंत्री ने महिला को एक हजार रुपये प्रदान किए। मुख्यमंत्री का यह सहज भाव स्थानीय स्तर पर छोटे व्यवसाय के माध्यम से आजीविका अर्जित करने वाली मीरा के श्रम, स्वाभिमान और स्वावलंबन के सम्मान का सुंदर संदेश भी दे गया।

17 सितंबर से शुरू होंगी गतिविधियां, 51 हजार दीये गौरी सरोवर और 2100 भिण्ड किले में जलेंगे

सेवा संकल्प अभियान: भिण्ड में 2.5 लाख दीयों से जगमगाएगा जिला

भिण्ड, साहस समाचार।

जिले में 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों की कार्ययोजना जारी कर दी गई है। अभियान की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम समय पर पूरा करने और उनकी पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

अभियान के पहले दिन 17 सितंबर को सुबह 6 से 8 बजे तक भिण्ड की सब्जी मंडी सहित अन्य निकायों में चिह्नित स्थानों पर स्वच्छता श्रमदान किया जाएगा। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित होगा, जिसमें 200 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है।

शाम 7 बजे 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम के तहत गौरी सरोवर किनारे 51 हजार और भिण्ड किला परिसर में 2100 दीये प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। पूरे जिले में करीब 2.5 लाख दीये जलाने का लक्ष्य रखा गया है। मेहगांव, लहार और गोहद में भी बड़े स्तर पर कार्यक्रम होंगे। दंदरौआ धाम, वनखण्डेश्वर मंदिर, रावतपुरा सरकार, काक्षी सरकार, गोहद किला, अटेर किला, आलमपुर छतरी और बैसली डेम सहित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर भी दीप प्रज्ज्वलन किया जाएगा।

कलेक्टर ने नगर परिषद के प्रत्येक वार्ड में 250 तथा नगर पालिका वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर 500 दीये स्वेच्छा से प्रज्ज्वलित करने की अपील की। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यक्रम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। दीप प्रज्ज्वलन के दौरान सुरक्षा और सावधानी बरतने पर भी विशेष जोर दिया गया।

अभियान के तहत 19 से 26 सितंबर तक 'सेवा चित्र' कार्यक्रम में चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें 'विकसित भारत-2047' की थीम रखी गई है। वहीं, 18 सितंबर को मौ में प्रस्तावित जन विश्वास शिविर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगा।

'सेवा सेतु' अभियान के तहत 2 से 10 अक्टूबर तक सभी विकासखंडों में हितग्राहीमूलक योजनाओं के संतृप्तिकरण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। इनमें समग्र, आधार पंजीयन एवं सुधार, आयुष्मान पंजीयन तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर रहेगा।

डिप्टी कलेक्टर एवं शहरी नोडल अधिकारी प्रदीप मिश्रा ने बताया कि 7 अक्टूबर को जिले की प्रत्येक विधानसभा में 'सेवा ज्योति कलश यात्रा' निकाली जाएगी, जिसका समापन भिण्ड के मेला ग्राउंड में होगा। वहीं, वडनगर से वाराणसी सेवा यात्रा का पहला चरण 22 सितंबर को इटावा से भिण्ड में प्रवेश करेगा और 23 सितंबर को मुरैना के लिए रवाना होगा। दूसरा चरण 23 सितंबर को जालौन से जिले में प्रवेश कर 24 सितंबर को ग्वालियर के लिए रवाना होगा।

गांधी जयंती के अवसर पर 2 से 10 अक्टूबर तक रक्तदान शिविर, स्वच्छता श्रमदान, वृक्षारोपण, मतदाता जागरूकता एवं पंजीयन, नशामुक्ति अभियान, स्वास्थ्य शिविर और योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। 4 अक्टूबर को भिण्ड पुलिस लाइन में सुबह 7 बजे योग एवं ध्यान सत्र तथा सुबह 8 बजे भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान कार्यक्रम होगा।

ग्रामीण नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीर सिंह चौहान ने संबंधित विभागों को कार्ययोजना के अनुसार गतिविधियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

सेवा संकल्प अभियान को जनभागीदारी से प्रभावी बनाएं: साव

रायपुर,एजेंसी।

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने मंगलवार को नगरीय निकायों को 17 सितंबर से शुरू हो रहे 'सेवा संकल्प अभियान' को व्यापक जनभागीदारी के साथ प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। साव ने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन से वर्चुअल बैठक के माध्यम से प्रदेश के नगर निगमों के महापौरों एवं आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के साथ अभियान की तैयारियों की समीक्षा की।

उन्होंने विभागीय समन्वय, जनभागीदारी, प्रचार-प्रसार और गतिविधियों के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाई जाए और विकसित भारत-2047 के संकल्प से लोगों को जोड़ा जाए। समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए योजनाओं से लाभार्थियों के जीवन में आए बदलावों को भी प्रमुखता से सामने लाया जाए।

साव ने अभियान की गतिविधियों के प्रभावी दस्तावेजीकरण के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक आयोजन की फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जाए। विशेष रूप से 'सेवा की कहानी' के तहत लाभार्थियों की प्रेरक कहानियों तथा योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलावों को सामने लाया जाए। अभियान के तहत 'आशीर्वाद का दीया', '25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत', 'नमो सेवा गाथा', 'आंगन का उत्सव', 'सेवा की कहानी', 'विकसित भारत संकल्प यात्रा', 'सेवा ज्योति यात्रा', 'सेवा-मेरा योगदान', 'सेवा सेतु अभियान', 'रंगोली राष्ट्र' और 'राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज' जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम चयन में 'फोकस' रोहित और हार्दिक पर

दक्षिणी अफ्रीका में 2027 एकदिवसीय विश्व कप के लिए सिर्फ एक साल से अधिक समय बचा है, रोहित का भविष्य एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है।

मुम्बई,एजेंसी। जब अजीत अगरकर के नेतृत्व वाला चयन पैनल वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से शुरू होने वाले तीन वनडे मैचों के लिए भारत की टीम चुनने के लिए बैठक करेगा, तो रोहित शर्मा और हार्दिक पंड्या पर ध्यान केंद्रित होगा। यह अगरकर के वर्तमान कार्यकाल की आखिरी चयन बैठक होगी, जो अक्टूबर की शुरुआत में समाप्त होने वाली है। दक्षिणी अफ्रीका में 2027 एकदिवसीय विश्व कप के लिए सिर्फ एक साल से अधिक समय बचा है, रोहित का भविष्य एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। रोहित ने स्पष्ट कर दिया है कि वह टूर्नामेंट में खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके आसपास का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है।

जुलाई में इंग्लैंड दौरे के दौरान पता चला कि चयनकर्ताओं ने रोहित

से कहा था कि वे उनसे आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं - सचिव देवजीत सैकिया के माध्यम से बीसीसीआई ने बाद में इस बात को खारिज कर दिया और कहा कि रोहित भारत की वनडे योजनाओं का हिस्सा बने रहेंगे। कार्डिफ़ में दूसरे वनडे में 47 गेंदों में 26 रन की पारी के बाद उनके वनडे भविष्य को लेकर चर्चा तेज़ हो गई। इंग्लैंड दौरे से पहले उन्होंने घरेलू मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ 16, 48 और 79 रन का स्कोर बनाया था। कुल मिलाकर मध्यक्रम, लेकिन रोहित ने लॉर्ड्स में अपनी सबसे हालिया वनडे पारी में शतक लगाया।

टीम में उनकी स्थिति की जांच की जा रही है क्योंकि चयन पैनल ने उनकी जगह अक्टूबर 2025 में भारत के वनडे कप्तान के रूप में शुभमन गिल को नियुक्त किया था, इससे कुछ समय पहले ही रोहित ने भारत को मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाया था। इसलिए, बुधवार की चयन बैठक उस प्रश्न पर स्पष्टता दे सकती है जिसके अब तक परस्पर विरोधी उत्तर मिले हैं। भारत के नंबर 1 सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने लगातार चोटों के कारण आईपीएल 2026 के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है।

उन्हें जून में अफगानिस्तान वनडे के लिए चुना गया था, लेकिन श्रृंखला से पहले उनके पैर में चोट लग गई थी। इससे पहले, वह पीठ की ऐंठन के कारण मुंबई इंडियंस के लिए चार मैच नहीं खेल पाए थे और ताजा झटका लगने पर वह बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कंडीशनिंग का काम कर रहे थे। हार्दिक को अगले सप्ताह फिटनेस टेस्ट से गुजरना है और उम्मीद है कि उन्हें मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन चयनकर्ता अभी भी उन्हें वापस लेने में अनिच्छुक हो सकते हैं, क्योंकि वह 50 ओवर के प्रारूप में भारत के संतुलन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।

इससे पुडुचेरी में 6 अक्टूबर से शुरू होने वाला भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए मैच उनकी वापसी का संभावित चरण हो सकता है। यह समझा जाता है कि चयनकर्ता चाहते हैं कि हार्दिक फिलहाल 50 ओवरों के प्रारूप पर ध्यान केंद्रित करें - और टी20 पर नहीं - 2027 विश्व कप को प्राथमिकता देते हुए।

युकी भांबरी भारत-कोरिया डेविस कप मुकाबले से बाहर

सियोल,एजेंसी। भारत को दक्षिण कोरिया के खिलाफ डेविस कप क्वालीफायर मुकाबले में अपने अहम युगल खिलाड़ी युकी भांबरी की कमी खलेगी क्योंकि यह अनुभवी खिलाड़ी जांघ की चोट के कारण बाहर हो गया है। इसके कारण टीम को इस महत्वपूर्ण मुकाबले से कुछ दिन पहले अपने युगल संयोजन पर फिर से विचार करना पड़ रहा है। इस मैच का विजेता फाइनल्स में पहुंचेगा भारत के कप्तान रोहित राजपाल ने पुष्टि की कि भांबरी दूसरे दौर के मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

राजपाल ने कहा, युकी भांबरी की जांघ की स्थिति ठीक नहीं है और हो सकता है कि वह डेविस कप खेलने के लिए उपलब्ध ना हों इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं कि हमारा संयोजन क्या होगा। हमें डेविस कप से एक हफ्ता पहले ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। युकी को अमेरिकी ओपन के मुख्य ड्रॉ के मैच से पहले दाहिनी जांघ में खिंचाव की समस्या हुई थी और तभी से कोरिया के खिलाफ मुकाबले में उनके खेलने को लेकर संदेह बना हुआ था।

युकी की गैरमौजूदगी भारत की युगल योजनाओं के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि राजपाल ने पहले उन्हें दक्षिणेश्वर सुरेश के साथ जोड़ी बनाने के लिए चुना था। बेंगलुरु में नीदरलैंड के खिलाफ पिछले डेविस कप मुकाबले में यह संयोजन काफी असरदार रहा था। राजपाल ने कहा, पिछली बार मैंने युकी और डीके (दक्षिणेश्वर) को साथ खिलाया था क्योंकि युकी की सबसे बड़ी ताकत उसका रिटर्न है और यही डीके की कमजोरी है। वहीं युकी की सर्विस उनकी कमजोरी है और डीके की सर्विस बहुत जबरदस्त है।

इस विपरीत संयोजन ने उन्हें एक बहुत मजबूत जोड़ी बना दिया था। युकी के रिटर्न कौशल और दक्षिणेश्वर की दमदार सर्विस और वॉली ने एक-दूसरे के खेल में मदद की।

ब्रेंडन टेलर ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड

हरारे,एजेंसी। जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर पहला वनडे मुकाबला खेला जा रहा है। पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में मैदान पर उतरने के साथ ही जिम्बाब्वे के विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने सचिन तेंदुलकर का सबसे लंबे वनडे करियर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टेलर ने रिटायरमेंट और आईसीसी के साढ़े तीन साल के निलंबन के बाद 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी। अब वह 2004 में अपने डेब्यू के बाद से 22 साल और 146 दिन तक वनडे क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है।

उन्होंने भारत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनका 1989 से 2012 तक 22 साल और 91 दिनों का शानदार वनडे करियर रहा। अब टेलर सबसे लंबे समय तक वनडे क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। टेलर जिम्बाब्वे के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। अपने वनडे करियर में टेलर अब तक 205 पारियों में 6,704 रन बना चुके हैं। वह जिम्बाब्वे की ओर से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इस सूची में उनसे आगे सिर्फ एंडी फ्लावर हैं।

श्री चरणी की महिला टी 20 बॉलिंग रैंकिंग में बड़ी छलांग

दुबई,एजेंसी। अपनी टीम के रिकॉर्ड आठवीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीतने के बाद, भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी महिला टी 20 प्लेयर रैंकिंग में बड़ा फ़ायदा हुआ है। श्री चरणी ने बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर अपनी स्थिति मज़बूत की है और शेफाली वर्मा बल्लेबाज़ों की टॉप छह रैंकिंग में वापस आ गई हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में 20 रन देकर 4 विकेट लेने के शानदार प्रदर्शन से, इस बाएं हाथ की स्पिनर ने पहली बार 800-पॉइंट का आंकड़ा पार करते हुए करियर की सर्वश्रेष्ठ 804 रेटिंग पॉइंट हासिल की हैं। यह महिला टी 20 प्लेयर रैंकिंग में बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों, दोनों में किसी भी भारतीय द्वारा हासिल की गई अब तक की सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट है।

इसने 2011 में बैटिंग रैंकिंग में मिताली राज के 780 पॉइंट के पिछले

रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। चरणी अब ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट द्वारा नवंबर 2018 में हासिल की गई महिला टी 20 गेंदबाज़ की अब तक की सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट से सिर्फ़ दो पॉइंट पीछे हैं। भारत के बॉलिंग अटैक को और फ़ायदा तब मिला जब दीप्ति शर्मा चार स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे नंबर पर आ गईं। उन्होंने एशिया कप में 14 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ के तौर पर अपना सफ़र पूरा किया। शानदार बॉलिंग प्रदर्शन के बाद तेज़ गेंदबाज़ नंदनी शर्मा 10 स्थान ऊपर चढ़कर 94वें नंबर पर पहुंच गई हैं, जबकि लेग-स्पिनर प्रेमा रावत ने इस हफ़्ते सबसे बड़ी छलांग लगाई है और 50 स्थान ऊपर चढ़कर 96वें नंबर पर पहुंच गई हैं।

नंदनी का प्रदर्शन काफ़ी किफायती रहा, उन्होंने प्रति ओवर सिर्फ़ 4.64 रन दिए। महिला टी 20 बैटिंग रैंकिंग में, शेफाली वर्मा के शानदार टूर्नामेंट प्रदर्शन की वजह से वह सातवें से छठे स्थान पर पहुंच गई हैं। एशिया कप में वर्मा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं। उन्होंने कुल 236 रन बनाए, जिसमें सेमीफ़ाइनल में 64 और फ़ाइनल में 68 रन शामिल थे। अब उनके 741 रेटिंग पॉइंट्स हैं - जो अक्टूबर 2021 के बाद से उनका सबसे अच्छा स्कोर है। वह अपनी टीम की साथी स्मृति मंधाना से सिर्फ़ एक पायदान और चार रेटिंग पॉइंट्स पीछे हैं। मंधाना पाँच पारियों में 213 रन बनाकर 745 पॉइंट्स के साथ पाँचवें स्थान पर हैं।

वर्मा ने ऑल-राउंडर्स की रैंकिंग में भी काफ़ी सुधार किया है; वह पाँच पायदान ऊपर चढ़कर 15वें स्थान पर पहुँच गई हैं और उनके रेटिंग पॉइंट्स 221 हो गए हैं, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ है।

बाबर आज़म की सात साल बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी

इस्लामाबाद,एजेंसी। बाबर आज़म मौजूदा प्रेसिडेंट्स ट्रॉफ़ी ग्रेड 1 फ़र्स्ट-क्लास टूर्नामेंट में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओजीडीसीएल) के लिए खेलेंगे। उन्हें टीम ने गेस्ट प्लेयर के तौर पर अपने साथ जोड़ा है। क्रिकइंफो को मिली जानकारी के मुताबिक़ पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान ने पीसीबी से उन्हें किसी टीम में शामिल करने का अनुरोध किया था, ताकि वह लंबे फ़ॉर्मेट में ख़ुद को तरोताज़ा रख सकें। इसके बाद बोर्ड ने ओजीडीसीएल के साथ उन्हें जोड़ा है। बाबर ने दिसंबर 2022 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में कोई शतक नहीं लगाया है। तब उन्होंने कराची में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ ड्रॉ रहे टेस्ट में 161 रन बनाए थे। 2023 की शुरुआत से टेस्ट में उनकी औसत 30.43 रही है, जो इस फ़ॉर्मेट में उनके करियर औसत से 12.55 रन कम है।

इस दौरान 39 पारियों में बाबर ने सिर्फ़ आठ अर्धशतक लगाए हैं। इसमें एक ऐसा दौर भी आया, जब वह लगातार 18 पारियों तक 41 रन से आगे नहीं बढ़ सके। हालांकि उनके पिछले पांच टेस्ट में चार अर्धशतक आए हैं। अपने आख़िरी टेस्ट शतक के बाद से उनका सबसे बड़ा स्कोर 88 रन रहा है, जो उन्होंने पिछले महीने वेस्टइंडीज़ दौरे के दूसरे और आख़िरी टेस्ट में जीत वाली पारी में बनाया था। उस जीत के साथ पाकिस्तान ने जुलाई 2023 के बाद पहली बार विदेश में टेस्ट मैच जीता और लगातार आठ विदेशी टेस्ट हार का सिलसिला भी ख़त्म किया था।

बिजनेस

असेन्सो खनन क्षेत्र के लिए टायर निर्माण का करेगी विस्तार

नई दिल्ली,एजेंसी। परिवहन से इतर विशेष उद्देश्य वाले वाहनों के लिए टायर बनाने वाली कंपनी असेन्सो ने खनन में काम आने वाले वाहनों के टायर निर्माण में क्षमता विस्तार के लिए 10 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है।

भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर ने जुटाया 1.4 अरब डॉलर का फंड: रिपोर्ट

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर ने अब तक कुल 1.4 अरब डॉलर का फंड जुटाया है, जिसमें से आधी से ज्यादा कैपिटल 2025 के बाद जुटाई गई है। यह जानकारी मंगलवार को जारी रिपोर्ट में दी गई। ट्रैकक्सन टेक्नोलॉजीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में 3,557 कंपनियां शामिल है।

शेयर बाजारों में लगातार दूसरी गिरावट, सेंसेक्स 778 अंक लुढ़का

दिसंबर 2026 तक निफ्टी के 26,200 तक पहुंचने का लगाया अनुमान।

मुंबई,एजेंसी। विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और बीएसई का सेंसेक्स 778 अंक नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 588 अंक ऊपर 75,369.63 अंक पर खुला और एक समय 655 अंक चढ़ गया था। हालांकि कुछ ही देर बाद बाजार में बिकवाली शुरू हो गई और सेंसेक्स 73,994 अंक तक टूट गया। इस प्रकार इसमें 1,375 अंकों का उतार-चढ़ाव देखा गया। अंत में सेंसेक्स 777.94 अंक (1.04 प्रतिशत) नीचे 74,003.82 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी कारोबार की समाप्ति पर 279.50 अंक यानी

1.19 प्रतिशत नीचे 23,118.60 अंक पर रहा।

बाजार में चौतरफा बिकवाली के बीच आईटी सेक्टर में लिवाली रही। निफ्टी आईटी सूचकांक 2.19 प्रतिशत ऊपर रहा। अन्य सभी सेक्टरों में बिकवाली का जोर रहा। रियल्टी समूह का सूचकांक 4.04 प्रतिशत, रसायन समूह का 3.42, धातु का 2.54 टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद का 2.41, मीडिया का 2.17, ऑटो का 2.01, वित्त का 1.83, बैंकिंग का 1.43, फार्मा का 1.30, तेल एवं गैस का 1.29 और स्वास्थ्य समूह का 1.17 प्रतिशत टूट गया। वृहत बाजार में मिडकैप-50 सूचकांक 2.08 फीसदी और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 2.43 प्रतिशत नीचे बंद हुआ।

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने की आशंका में लगभग सभी प्रमुख एशियाई शेयर बाजार लाल निशान में रहे। यूरोपीय बाजार भी गिरावट में खुले। सेंसेक्स की कंपनियों में बीईएल का शेयर सबसे ज्यादा छह प्रतिशत, इंडिगो का चार प्रतिशत और टाइटन, बजाज फिनसर्व तथा अडानी पोर्ट्स के तीन-तीन प्रतिशत लुढ़क गए। महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय स्टेट बैंक, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, इटरनल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और पावरग्रिड के शेयर दो से तीन प्रतिशत नीचे बंद हुए। आईसीआईसीआई बैंक।

रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएंडटी और मारुति सुजुकी के शेयर एक से दो प्रतिशत तक गिरे। एनटीपीसी, आईटीसी और सन फार्मा के शेयर भी नुकसान में रहे। सूचना एवं प्रौद्योगिकी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शेयर करीब चार प्रतिशत और इंफोसिस का साढ़े तीन प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा। टेक महिंद्रा और टीसीएस के शेयर दो प्रतिशत से ज्यादा मजबूत हुए। एचडीएफसी बैंक का शेयर सवा फीसदी मजबूत हुआ।

एसआईसी ने बीमा दावों के स्थिति के बारे में एसएमएस अलर्ट शुरू किए

नई दिल्ली,एजेंसी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने बीमाकृत व्यक्तियों को उनके दावों की स्थिति के बारे में ऑटोमैटिक अपडेट देने के लिए एसएमएस-आधारित सुविधा शुरू की है। इससे लाभार्थियों को अपने केस का पता लगाने के लिए शाखा कार्यालयों में जाने की जरूरत कम हो जाएगी। एक आदेश में, ईएसआईसी ने कहा कि दावा निपटारों के अलग-अलग चरण पर बीमाकृत लोगों को समय पर जानकारी देने के लिए इस सुविधा को अपने सिस्टम में शामिल किया गया है।

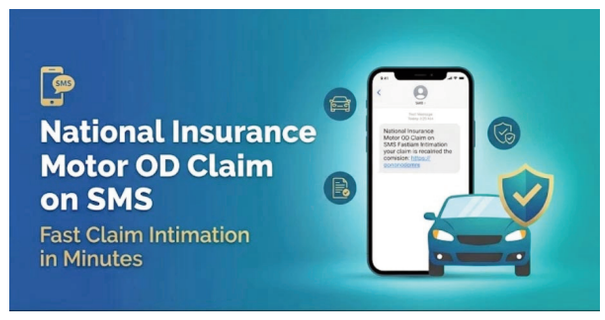

कॉरपोरेशन की लाभार्थी शाखा की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत, जब कोई दावा दाखिल, खारिज या मंज़ूर किया जाएगा, तो बीमित व्यक्तियों को अपने-आप एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे। इस कदम का मकसद क्लेम प्रोसेस करने में पारदर्शिता लाना और लाभार्थियों को उनके क्लेम की प्रगति और स्थिति के बारे में जानकारी देते रहना है।

ईएसआईसी ने कहा कि अभी बीमाकृत लोगों को अपने दावे के निपटारे या उसकी प्रगति के बारे में जानकारी पाने के लिए संबंधित शाखा में जाना पड़ सकता है। एसएमएस सुविधा का मकसद लाभार्थियों को सीधे ऐसी जानकारी देना है।

कॉरपोरेशन ने अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक,प्रभारी संयुक्त निदेशक,प्रभारी उप निदेशक,क्षेत्रीय कार्यालय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय से इस सुविधा पर ध्यान देने को कहा है। जानकारी में कहा गया है कि इस पहल से बीमित लोगों को अपने दावों के निपटारे के बारे में समय पर जानकारी मिल सकेगी।कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में चलाई जाने वाली एक केंद्र सरकार की स्कीम है।

यात्री वाहनों की थोक बिक्री अगस्त में 36.5 प्रतिशत बढ़कर 4.39 लाख के पार

नई दिल्ली,एजेंसी। घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की थोक बिक्री अगस्त में साल-दर-साल 36.5 प्रतिशत की जबरदस्त तेजी के साथ 4.39 लाख को पार कर गयी। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम ने मंगलवार को वाहनों की बिक्री के आंकड़े जारी किए। उसने बताया कि यात्री वाहनों, दुपहिया और तिपहिया की बिक्री ने अगस्त 2026 में किसी भी साल की अगस्त की बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। यात्री वाहनों की बिक्री में 36.5 प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह 4,39,309 इकाई पर रही।

दुपहिया की बिक्री 10.5 फीसदी बढ़कर 20,34,698 पर पहुंच गई। इसमें पिछले साल अगस्त के मुकाबले स्कूटरों की बिक्री में 23.8 प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह 8,55,715 इकाई रहा। वहीं, मोटरसाइकिलों की बिक्री 11,33,047 इकाई रही। इसमें 2.4

प्रतिशत की वृद्धि हुई है। महीने के दौरान देश में कुल 45,936 मोपेड बिके। इनकी बिक्री 4.7 प्रतिशत बढ़ी है। गत अगस्त में देश में कुल 93,764 तिपहिया बिके जो एक साल पहले के मुकाबले 22.8 प्रतिशत अधिक है। इनमें तिपहिया यात्री वाहनों की बिक्री 22.4 फीसद बढ़कर 78,680 इकाई रही। मालवाहक तिपहिया की बिक्री भी 34.9 प्रतिशत बढ़कर 13,320 इकाई पर पहुंच गई। ई-रिक्शा की बिक्री छह फीसदी घटकर 1,264 इकाई और ई-कार्ट की 38.3 प्रतिशत गिरकर 500 इकाई रह गई।

सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने आंकड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश का वाहन उद्योग इस समय मजबूत दौर से गुजर रहा है। अगस्त में रही जबरदस्त तेजी में पिछले साल अगस्त की कमजोर बिक्री का भी योगदान है। कुल मिलाकर मांग परिदृश्य मजबूत बना हुआ है।

एनएसई के आईपीओ के लिए अप्रत्याशित मांग: आशीष चौहान

नई दिल्ली,एजेंसी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने मंगलवार को दावा किया कि एनएसई के 17 सितंबर से आ रहे प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए अप्रत्याशित मांग है। चौहान ने आईपीओ से पहले यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न के उत्तर में कहा, मांग अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा कि पहले देश और विदेश के मुख्य (एंकर) निवेशकों के लिए अधिकतम सीमा 6,000 करोड़ रुपये रह गई है। इसलिए मांग काफी अधिक है। उल्लेखनीय है कि एनएसई का आईपीओ 17 सितंबर से 21 सितंबर तक खुला रहेगा। कंपनी

बीएसई पर सूचीबद्ध हो रही है।

एंकर निवेशकों से मिले निवेश की घोषणा एक दिन पहले यानी 16 सितंबर को की जाएगी। कंपनी के एक रुपये अंकित मूल्य वाले 247.50 करोड़ शेयर में से मौजूदा निवेशक 12,64,36,650 करोड़ शेयर बेच रहे हैं। यह कंपनी के कुल शेयर का 5.11 प्रतिशत है। शेयरों के लिए मूल्य का दायरा 1,700 रुपये से 1,785 रुपये तैयार किया गया है। निवेशक कम से कम आठ शेयरों और उसके बाद आठ के गुणांक में शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। मूल्य दायरे की ऊपरी सीमा पर आईपीओ का आकार 22,569 करोड़ रुपये का होगा। इसके देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा आईपीओ होने की उम्मीद है।

चौहान ने बताया कि कंपनी कोई नया शेयर नहीं ला रही है। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) है। इसका मुख्य कारण यह है कि कंपनी लगातार मुनाफे में रह रही है और इसके पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। शेयरधारकों में भारतीय स्टेट बैंक, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, अरंदा इन्वेस्टमेंट्स (मॉरीशस), एमएस स्ट्रेटेजिक (मॉरीशस), द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी शामिल हैं।

एनएसई के सीईओ ने बताया कि आईपीओ आने के बाद कंपनी के शेयरों की खरीद-बिक्री में आसानी हो जाएगी। कंपनी के सूचीबद्ध न होने के कारण शेयरों के सौदे के लिए उचित मूल्य पर पहुंचना मुश्किल होता था। अब एक शेयर बाजार के मूल्य से संदर्भ के लिए एक दर मिल जाएगी।

उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग की संख्या के आधार पर एनसई दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। इस पर 13 करोड़ से अधिक यूनीक निवेशक सूचीबद्ध हैं। एक दिन में 2,200 करोड़ तक ट्रेडिंग होती है। कंपनी अधिशेष आय का ज्यादातर हिस्सा निवेशकों में बांट देती है। आईपीओ में पात्र संस्थागत निवेशक अधिकतम 50 प्रतिशत शेयर खरीद सकेंगे। गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए कम से कम 15 प्रतिशत और खुदरा निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत शेयर आरक्षित होंगे। चौहान ने भारतीय शेयर बाजार के बारे में कहा कि एनएसई में ट्रेडिंग शुरू होने के बाद से 33 साल में इसका वेल्थ 120 गुणा हो गया है।

बाजार की वृद्धि में युवाओं और प्रौद्योगिकी का सबसे अधिक योगदान रहा है। युवा आबादी निवेश करने में यकीन करती है क्योंकि उनकी मांग अधिक है।

रोहित रॉय के 'डस्टबिन मीडियम' वाले बयान से चाहत खन्ना सहमत

मुंबई। एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने टीवी इंडस्ट्री को लेकर चल रही बहस के बीच रोहित रॉय के हालिया विवादित बयान पर अपनी राय रखी है। रोहित ने अपने एक इंटरव्यू में टीवी को 'डस्टबिन मीडियम' तक कह दिया था और मौजूदा टीवी कंटेंट की क्वालिटी, कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी पर सवाल उठाए थे। अब चाहत खन्ना ने भी माना है कि अगर बात कहानी और क्रिएटिविटी की हो तो टीवी इस समय फिल्मों और ओटीटी से काफी पीछे है।

हालांकि, चाहत ने यह भी साफ किया कि उन्होंने रोहित का पूरा इंटरव्यू नहीं देखा है, इसलिए वह उनके पूरे बयान पर कमेंट नहीं करना चाहतीं। आईएएनएस से खास बातचीत में चाहत ने कहा, "मैं खुद टीवी से आई हूं और इस माध्यम की बहुत इज्जत करती हूं। टीवी ने मुझे एक एक्टर के तौर पर मजबूत बनाया है। यहां एक्टर्स को लंबे समय तक लगातार शूटिंग करनी पड़ती है। कई बार 12 से 15 घंटे तक शूट करना सामान्य बात लगती है। फिल्मों में काम करने का तरीका अलग है और वहां क्रिएटिविटी को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। वहीं ओटीटी में भी कहानी की डिटेलिंग और क्रिएटिविटी का तरीका टीवी से काफी अलग है।"

एक्ट्रेस ने रोहित रॉय की बात के उस हिस्से से सहमति जताई, जिसमें उन्होंने टीवी के मौजूदा कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी पर सवाल उठाए थे। चाहत ने कहा, "अगर कहानी और क्रिएटिविटी की बात की जाए तो टीवी को अभी काफी आगे जाने की जरूरत है। टीवी का कंटेंट मास ऑडियंस को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। दर्शक जिस तरह की कहानियां और शोज देखना चाहते हैं, मेकर्स भी उसी डिमांड के हिसाब से कंटेंट बनाते हैं। यह पूरी तरह बिजनेस का हिस्सा है। अगर किसी तरह का कंटेंट बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, तो उसे बार-बार बनाए जाने के पीछे एक मार्केट डिमांड भी होती है।"

चाहत ने अपने करियर का उदाहरण देते हुए बताया, "मुझे कई ऐसे टीवी शोज के ऑफर मिलते हैं, जिनसे मैं खुद कनेक्ट नहीं कर पाती। खासतौर पर 'नागिन' जैसे शोज, जिनसे मैं जुड़ नहीं पाती। अगर कोई एक्टर क्रिएटिव है तो उसके लिए टीवी के कुछ मौजूदा कॉन्सेप्ट से जुड़ना मुश्किल हो सकता है।"

चाहत ने आगे कहा, "अगर मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स से जुड़ पाती तो शायद करियर के लिए चीजें और बेहतर होती। जो चीज मुझे पसंद आती है और जिससे मैं खुद जुड़ाव महसूस करती हूं, वही काम करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है।"

गौरतलब है कि रोहित रॉय ने हाल ही में एक इंटरव्यू में टीवी और फिल्मों के बीच के फर्क पर बात की थी। टीवी के पॉपुलर चेहरों में शामिल रहे रोहित ने कहा था कि मौजूदा समय में टीवी पर आने वाला काफी कंटेंट जल्दी भुला दिया जाता है और कई शोज में एक जैसे कॉन्सेप्ट दोहराए जाते हैं। उन्होंने टीवी को 'डस्टबिन मीडियम' बताते हुए इसकी क्रिएटिविटी पर सवाल उठाया था।

'मां के बिना जिंदगी', सांवी के किरदार को समझने के लिए जान्हवी सोनी ने दोस्त की कहानी से ली मदद

मुंबई। टीवी एक्ट्रेस जान्हवी सोनी इन दिनों अपने नए शो 'सयोनी' को लेकर चर्चा में हैं। शो में वह सांवी नाम की एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही हैं, जिसकी जिंदगी मां के प्यार के बिना गुजरी है। सांवी का किरदार उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसमें एक ऐसी लड़की की भावनाओं को समझना था, जिसने बचपन से ही मां के साथ का अनुभव नहीं किया। हालांकि, इस किरदार को समझने के लिए जान्हवी को अपने आसपास ही एक ऐसी कहानी मिल गई, जिससे वह काफी हद तक जुड़ पाईं।

अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए जान्हवी ने कहा, "मैंने खुद सांवी जैसी स्थिति का सामना नहीं किया है, लेकिन मेरी एक करीबी दोस्त बचपन से अपनी मां के बिना बड़ी हुई है। वह अपनी मौसी को ही मां की तरह मानती हैं और दोनों के बीच के रिश्ते को मैंने बहुत करीब से देखा है। ऐसे में मेरे मन में अक्सर यह सवाल आता था कि बचपन में स्कूल जाने, एग्जाम देने या जिंदगी के खास पलों को मां के बिना जीना मेरी दोस्त के लिए कैसा रहता होगा।"

'सयोनी' में सांवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वह एक अनाथालय में पली-बढ़ी है और बचपन से मां के प्यार और परिवार के उस अपनापन से दूर रही है, जिसकी जरूरत हर बच्चे को होती है। हालांकि, उसकी जिंदगी में उसकी मौसी एक अहम जगह रखती हैं। समय के साथ मौसी ही उसके लिए मां जैसी बन जाती हैं और उसकी सबसे बड़ी इमोशनल सपोर्ट बनती हैं।

जान्हवी ने कहा, "अनाथालय में रहने वाले बच्चों के लिए भी कभी-कभी कोई एक ऐसा व्यक्ति बेहद खास बन जाता है, जिससे वे दिल से जुड़ जाते हैं। वह इंसान उनके लिए परिवार जैसा बन जाता है और उन्हें सुरक्षा, अपनापन और भावनात्मक सहारा देता है। सांवी के किरदार को समझते समय मैंने इसी भावना को पकड़ने की कोशिश की।"

किरदार की तैयारी के बारे में जान्हवी ने कहा, "मैंने अपनी दोस्त की जिंदगी में जो कुछ देखा और समझा, उसे सांवी के किरदार से जोड़ने की कोशिश की। दोस्त के अनुभव को करीब से देखने की वजह से मैं सांवी के इमोशंस तक पहुंच पाईं और समझ सकीं कि उसके लिए मां जैसी शख्सियत को ढूंढना इतना जरूरी क्यों है। सांवी के लिए यह सिर्फ मां का रिश्ता पाने की चाहत नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में एक ऐसे इंसान को पाने की जरूरत है, जिसके साथ उसे परिवार और अपनेपन का एहसास हो।"

सर्गुन मेहता के प्रोडक्शन हाउस ड्रीमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रहे इस शो से रश्मि देसाई भी टीवी पर वापसी कर रही हैं। शो में जान्हवी सोनी और गौतम सिंह विग भी अहम भूमिकाओं में हैं। हाल ही में रिलीज हुए प्रोमो में जान्हवी और गौतम की झलक देखने को मिली।'सयोनी' का प्रीमियर 23 सितंबर को स्टार प्लस और जियोहॉटस्टार पर होगा।

गणेश चतुर्थी पर डेजी शाह ने किया बप्पा का स्वागत, कहा-आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है

मुंबई। अभिनेत्री डेजी शाह ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपने घर में गणपति बप्पा का स्वागत किया। अभिनेत्री का मानना है कि यह त्योहार उनके घर में सकारात्मकता लाता है। साथ ही भगवान गणेश के आगमन से उनके घर का माहौल अच्छा बन जाता है।

अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में गजानन महाराज की पूजा के बारे में बताते हुए कहा, 'बप्पा वहीं हैं, हम भी वहीं हैं। बस भावनाएं और खुशियां नई हैं। जब भी बप्पा घर आते हैं तो हमें लगता है कि घर में एक अलग ही वाइब है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है।'

अभिनेत्री डेजी शाह ने बताया कि गणपति की मूर्ति उनके घर में सिर्फ डेढ़ दिन के लिए रहती है। वह बप्पा के लिए काफी खास पकवान बनवाती हैं। उन्होंने कहा, 'गुजराती में हम एक लड्डू बनाते हैं, जो गेहूं के आटे और गुड़ से बनता है। हर साल हम इसे बप्पा के लिए बनाते हैं और क्योंकि बप्पा सिर्फ डेढ़ दिन के लिए आते हैं, हम यह ध्यान रखते हैं कि जो भी भक्त हमारे घर आते हैं, उन्हें वही घर का बना प्रसाद मिले जो हम बाबा के लिए बनाते हैं।'

डेजी शाह ने कहा, 'आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। अगर और कुछ नहीं, तो आपकी सोच, नजरिया मायने रखता है। अगर कोई आपको ट्रोल करता है, तो आप उसे इग्नोर करके चुप करा सकते हैं और अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं और बता सकते हैं कि आप सही हैं या गलत।'

विदेश

राष्ट्रपति ली ने की तुर्कमेनिस्तान की सराहना

सोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने मंगलवार को तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्दिमुहामेदोव का आभार व्यक्त कयिा। उन्होंने ईरान से दक्षिण कोरियाई नागरिकों को सुरक्षित निकालने में तुर्कमेनिस्तान की मदद की सराहना की। यह निकासी इस साल अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद की गई थी।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ट्रंप की अपील

वॉशिंगटन। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (स्थानीय समय के अनुसार) ट्रंप प्रशासन को नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनावों के लिए मेल बैलेट पर नए और व्यापक नियम लागू करने से रोक दिया। कोर्ट ने उस आपातकालीन अपील को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी।

यमन में जारी लड़ाई की वजह से लोग घर छोड़ने को मजबूर : संयुक्त राष्ट्र

यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) से जुड़े मानवीय सहायता संगठनों ने चेतावनी दी है कि यमन में जारी लड़ाई लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। इससे आम नागरिकों की मौत और घायल होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं, पहले से दबाव में चल रहे राहत कार्यों पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने सोमवार (स्थानीय समयानुसार) बताया कि सितंबर की शुरुआत से अब तक यमन में फिर से भड़की हिंसा के कारण कम से कम 1.25 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है।सन्हिुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने इस महीने के पहले दो हफ्तों में 40 आम नागरिकों के हताहत होने की पुष्टि की है। इनमें 8 लोगों की मौत हुई है और 32 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में आधे और घायल होने वालों में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं।

ओसीएचए ने कहा कि बेहद मुश्किल हालात के बावजूद संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगी संगठन राहत कार्य जारी रखे हुए हैं। शनिवार तक हजारों परिवारों को सहायता पहुंचाई जा चुकी थी। हालांकि, राहत सामग्री की भारी कमी हो रही है और उपलब्ध फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।ओसीएचए ने कहा, 'सुरक्षा संबंधी जोखिमों के कारण राहत एजेंसियों की आवाजाही और सहायता पहुंचाने का काम गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।'

संस्था ने बताया कि यमन के पश्चिमी तट के कई इलाकों में मानवीय सहायता पहुंचाने और राहत कर्मियों की आवाजाही फिलहाल रुकी हुई है। कई महत्वपूर्ण सड़कें या तो बंद हैं या उन पर यात्रा करना संभव नहीं है।ओसीएचए ने एक बार फिर सभी पक्षों से अपील की कि वे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करें और राहत सहायता को सुरक्षित तथा बिना किसी रुकावट के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने दें।

इस महीने की शुरुआत में यमन की सरकारी सेना ने कहा था कि पश्चिमी तट पर हूती विद्रोहियों के साथ एक महीने तक चली लड़ाई में 500 से ज्यादा सैनिक मारे गए और लगभग 1,500 घायल हुए।यह लड़ाई उस समय तेज हो गई जब हूती समूह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाब-अल-मंदब स्ट्रेट की ओर बड़े पैमाने पर बढ़त बनाने की कोशिश की।

सरकारी समर्थक नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेज ने सरकारी चैनल अल-जौम्हूरिया टीवी पर जारी बयान में कहा कि ये हताहत 9 अगस्त से 10 सितंबर के बीच दर्ज किए गए।बयान में दावा किया गया कि इस दौरान 1,000 से अधिक हूती लड़ाके मारे गए और हजारों घायल हुए। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

ईरान के दक्षिणी तट पर मछली पकड़ने वाली दो नौकाओं पर ड्रोन हमला

तेहरान। ईरान के दक्षिणी तट के पास सोमवार रात दो मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर ड्रोन हमला हुआ। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के अनुसार, इस घटना के बाद से कई मछुआरे लापता हो गए हैं। यह हमला दक्षिणी बंदरगाह शहर कारगन के तट के पास और लारक द्वीप के आसपास हुआ।

होर्मोजगान प्रांत के राजनीतिक और सुरक्षा मामलों के उप-गवर्नर अहमद नफीसी ने बताया कि लापता मछुआरों की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है।उन्होंने कहा कि घटना की जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद अधिक जानकारी साझा की जाएगी।इसी बीच, इससे पहले ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की नौसेना ने बताया था।

मेक्सिको के आंतरिक मामलों में विदेशी दखल मंजूर नहीं: राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबौम

मेक्सिको सिटी। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबौम ने एक बार फिर कहा है कि उनकी सरकार देश के आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी दखल या हस्तक्षेप को मंजूर नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ संबंध सहयोग और तालमेल पर आधारित होने चाहिए।

सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेनबौम ने उन लोगों की आलोचना की जो, उनके मुताबिक, विदेशी हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अमेरिका के कुछ वर्गों और मेक्सिको के विपक्षी दलों में भी मौजूद हैं।उन्होंने कहा, ₹हम हमेशा इस सिद्धांत का बचाव करेंगे कि किसी तरह का हस्तक्षेप या दखल नहीं होना चाहिए। सिर्फ सहयोग और समन्वय होना चाहिए और वह भी बिना किसी अधीनता के।

ऑस्ट्रेलिया में एआई से जुड़े खतरों के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणाली की कमी: इंटेलिजेंस प्रमुख

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की साइबर खुफिया एजेंसी के प्रमुख की ओर से चेतावनी दी गई है कि देश को एआई से उत्पन्न खतरों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलियाई सिग्नल्स डायरेक्टरेट (एएसडी) की डायरेक्टर-जनरल एबिगेल ब्रैडशॉ ने सोमवार को कैनबरा में एक समिट में कहा कि एआई हमले सरकारों और व्यवसायों की ओर से इस्तेमाल की जा रही पुरानी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, उन्होंने संगठनों से एआई को एक सुरक्षात्मक टूल के तौर पर अपनाने का आग्रह किया और कहा कि खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को शुरुआती जोखिमों की पहचान करने के लिए एआई कंपनियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब ऑस्ट्रेलियाई राजनेता और एआई कंपनियों के अधिकारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती चेतावनियों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि एआई विकसित करने की दौड़ मानवता की उसे नियंत्रित करने की क्षमता से आगे निकल सकती है। ब्रैडशॉ ने कहा, 'अभी हमारे पास जिस चीज की कमी है (जो साइबर संदर्भ में तो है लेकिन एआई संदर्भ में अभी तक औपचारिक रूप से नहीं है) वह है एक शुरुआती चेतावनी प्रणाली।'

कैनबरा में यह समिट एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई की ओर से शनिवार को उद्योग से गति धीमी करने और तीसरे पक्ष के मूल्यांकनकर्ताओं से सुरक्षा उपायों के प्रति मॉडलों के अनुपालन को सत्यापित करने का आग्रह करने के कुछ दिनों बाद आयोजित की गई थी। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एक्सएआई के एलन मस्क की ओर से अमोदेई की बातों से सहमति जताई गई।

इसके जवाब में, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए ऑस्ट्रेलियाई सहायक मंत्री एंड्रयू चार्लटन ने सोमवार को कहा कि वह नहीं चाहते कि एआई के लिए सुरक्षा नियम (गार्डरेल्स) तय करने की पूरी जिम्मेदारी केवल टेक्नोलॉजी कंपनियों या संयुक्त राज्य अमेरिका की हो।एंड्रयू चार्लटन ने आगे कहा, ₹मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात की ज्यादा परवाह करनी चाहिए कि अलग-अलग मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) क्या कहते हैं या अलग-अलग अधिकारी क्या चाहते हैं।